04 - भारत के पास है विकास के विनाश का विकल्प

05 - जगन्नाथ रथयात्रा :भारत की राष्ट्रीय एकत्व का जीवंत प्रतीक

06 - शाहपुर के साप्ताहिक बाजार में डलवाई मुरम, बजरी

07 - खाद-बीज दुकानों का करें नियमित निरीक्षण : कलेक्टर



A Daily News Magazine
भोपाल
गुरुवार, 16 जुलाई, 2026

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 314, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2



subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews


प्रसंगवश

# एआई के चलते गूगल व विकीपीड्डिया का भविष्य भी खतरे में है

**संजय दुबे**

जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नुकसानों के संदर्भ में जिस बात पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, वह यह है कि इस दौड़ में इंसान अकेला नहीं है। इंटरनेट को उसकी मौजूदा शक्ल देने वाले सबसे बड़े टेक दिग्गजों – गूगल, क्वोरा और विकीपीडिया – को भी अब एआई के चलते अपना धंधा छिन जाने का खतरा सता रहा है। अब तक जब भी कोई सवाल होता तो हम गूगल से पूछा करते थे। कोई तथ्य चाहते, तो विकीपीडिया था। और अगर कोई व्यक्तिगत अनुभव या जानकारी जरूरी लगती, तो क्वोरा का सहारा था। ये प्लेटफॉर्म्स सालों से इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी पाने के सबसे लोकप्रिय ठिकाने रहे हैं।

आज जानकारी का एक नया तंत्र बन रहा है। एआई टूल्स – जैसे चैटजीपीटी, जैमिनी और क्लॉड – इसके केंद्र में हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस एआई क्रांति को कभी गूगल ने बढ़ावा दिया था, आज उसी ने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं है, इंटरनेट पर जानकारी के बहाव का पूरा ढांचा ही खामोशी से उलट-पलट हो रहा है।

सालों तक गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया का मेन गेट था। गूगल आपको दिखाता था कि जवाब कहां मिल सकता है, किसी मददगार लाइब्रेरियन की तरह। लेकिन एआई आधारित टूल्स के आने के बाद यह मॉडल दबाव में आ गया। चैटजीपीटी जैसे टूल्स ने दिखा दिया कि लोग हमेशा वेबसाइट्स की लंबी लिस्ट नहीं चाहते। वे बिना इधर-उधर भटके अपने सवाल का सीधा, सुथरा, संक्षिप्त और समझदार जवाब चाहते हैं। यानी लोग अब लाइब्रेरियन नहीं, एक रिसर्च असिस्टेंट चाहते हैं। ऐसा असिस्टेंट जो खुद किताबें छाने, और फिर उनका सार हमारे सामने रख दे।

खुद को ज़िंदा रखने के लिए गूगल ने भी अपना तरीका बदल लिया है। अब उसके एआई ओवरव्यूज़ वही काम करते हैं, जो दूसरे एआई टूल्स करते हैं – यानी सवालों का फौरन जवाब देना। ऐसे में अक्सर यूज़र्स को लिंक पर क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस प्रक्रिया में गूगल ने उन प्लेटफॉर्म्स को ही निगलना शुरू कर दिया है, जिन पर उसका सर्च इंजन टिका हुआ है – विकीपीडिया, क्वोरा, रेडिट और अनगिनत ब्लॉग्स और फोरम्स।

पहले अगर आप यह टाइप करते कि 'टोक्यो में रहने का अनुभव कैसा है?' तो क्वोरा की कोई चर्चा, विकीपीडिया का पन्ना या किसी स्वतंत्र वेबसाइट का लिंक सामने आता था। लेकिन अब पेज के सबसे ऊपर एक बढ़िया-सा एआई सारांश मिल जाता है। क्वोरा, रेडिट, विकीपीडिया और बाकी स्वतंत्र ब्लॉग्स के लिंक नीचे खिसक जाते हैं। कई बार ये लिंक्स हमें दिखते तक नहीं हैं। इसका असर जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। हमारे बारे में

पहले क्वोरा की।उसका पूरा मॉडल इसी पर टिका है कि लोग गूगल पर सवाल सर्च करें, क्वोरा के पन्नों तक पहुंचें, वहां दूसरों के व्यक्तिगत जवाब पढ़ें और चाहें तो अपना जवाब भी लिखें। लेकिन गूगल से ट्रैफिक कम होने का मतलब है कम पाठक। पाठक कम होंगे तो जवाब देने वालों की संख्या भी घटेगी। इसका असर उस इंटरनेट कम्युनिटी पर पड़ेगा, जो क्वोरा के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी है। ट्रैफिक कम होने का मतलब कम सब्सक्राइबर, कम विज्ञापन, और कम कमाई भी है।क्वोरा को भी इसका एहसास है। इसी वजह से उसने अपना खुद का एआई प्लेटफॉर्म – 'पो' – शुरू किया है। लेकिन यह और भी उलझनभरी स्थिति है। क्वोरा जितना ज़्यादा एआई पर निर्भर होगा, उतना ही उसका पुराना कम्यूनिटी आधारित मॉडल कमजोर होता जाएगा। फिर वह भी बाकी एआई टूल्स की भीड़ में एक और टूल बनकर अपनी पहचान खो सकता है।

विकीपीडिया के सामने भी ऐसी ही – बल्कि इससे कहीं ज़्यादा पेंचीदा – चुनौती है। क्वोरा की तरह वह भी कंटेंट और कमाई (जो दान के ज़रिए आती है), दोनों के लिए अपने पाठकों पर ही निर्भर है। लेकिन जब एआई टूल्स सीधे-सीधे तथ्यात्मक सवालों के जवाब देने लगें, या गूगल के एआई ओवरव्यूज़ की वजह से लोग विकीपीडिया पर ही न आएं, तो इससे न सिर्फ उसके ट्रैफिक पर असर पड़ता है, बल्कि बड़े पैमाने पर भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट तैयार करने की उसकी क्षमता भी कमजोर होती है। और विकीपीडिया का ढांचा ऐसा है कि वह खुद एआई टूल बन नहीं सकता। उसका ओपन, कम्युनिटी-आधारित और गैर-व्यावसायिक मॉडल एआई-जनित कंटेंट के लिए बना ही नहीं है।

लेकिन एआई की इस लहर को नज़रअंदाज़ करना भी मुमकिन नहीं है। भविष्य में जब बड़ी मात्रा में ऑनलाइन कंटेंट एआई से ही लिखा जाने लगेगा, तब विकीपीडिया के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि किसे भरोसेमंद स्रोत माना जाए और किसे नहीं। क्या तब वह एआई-जनित लेखों को भी स्रोत मानना शुरू कर देगा?

यह सवाल विकीपीडिया के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसकी पहचान ही इस बात पर टिकी है कि वह किसी जानकारी के लिए कितनी विश्वसनीय और प्रमाणित सूचनाओं का हवाला देता है। असली खतरा इंटरनेट के पूरे नॉलेज इकोसिस्टम की सेहत पर मंडरा रहा है।

सालों तक इंटरनेट एक अव्यवस्थित लेकिन जीवंत कंटेंट नेटवर्क बना रहा। बड़े न्यूज़रूम, यूनिवर्सिटीज़, जुनूनी ब्लॉगर, छोटे-छोटे फोरम और स्वतंत्र एक्सपर्ट इसका महत्वपूर्ण हिस्सा थे। गूगल सर्च वह दरवाज़ा था, जो इन सबको लोगों के सामने लाने का काम किया करता था। बेशक यह सिस्टम परफेक्ट नहीं था और इसमें एसईओ के खेल और क्लिकबेट या कमजोर कंटेंट की गड़बड़ियां थीं। लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप से यह एक खुली व्यवस्था थी। अब गूगल समेत अलग-अलग एआई टूल्स पर जो एआई सारांश दिखते हैं, वे जानकारी के इस बहाव को कुछ गिने-चुने बड़े और 'आधिकारिक रूप से भरोसेमंद' स्रोतों (सरकारी वेबसाइटें, बड़ी मीडिया संस्थाएं और अकादमिक पब्लिशर) तक समेट देने का खतरा पैदा कर रहे हैं।

इससे एसईओ पर टिका घटिया कंटेंट तो कमज़ोर पड़ेगा, जो बुरा नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ईमानदारी से, सोच-समझकर लिखने वाले स्वतंत्र क्रिएटर्स का हौसला भी टूट सकता है। अगर लोग ऐसी सामग्री पढ़ना, देखना और उसका समर्थन करना छोड़ देंगे, तो फिर कोई ढंग का कुछ लिखेगा या रचेगा ही क्यों?

ऐसे में इंटरनेट एआई-जनित शोर-शराबे से भर सकता है। और इससे नुकसान सिर्फ यूज़र्स का नहीं, खुद एआई का भी होगा, जो अपनी ट्रेनिंग और बेहतर होने के लिए अच्छे और मौलिक इंसानी कंटेंट पर निर्भर है। और यह ख़तरा बहुत बड़ा है। अगर एआई टूल्स इसी तरह बिना संदर्भों और स्रोतों वाला सारांश देते रहे, तो हम वह चीज़ ही खो देंगे जिसने इंटरनेट को अब तक एक कॉर्पोरेट और बंद जानकारियों वाले गढ़ में तब्दील होने से बचाकर रखा था।

**(सत्याग्रह में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)**

# आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के सर्वांगीण विकास की प्रथम पाठशाला : मुख्यमंत्री

### मुख्यमंत्री ने सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन कर हितलाभ किए वितरित

### मुख्यमंत्री ने उज्जैन में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में कन्याओं को झूला झुलाया

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के सर्वांगीण विकास की प्रथम पाठशाला है। सरकार द्वारा छोटे बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीएसआर फंड से बनाए गए सदावल में स्थित इस आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये गये है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा निरंतर इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से विकास किया जा रहा है, जिससे निरंतर उनकी दशा में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के विकास एवं पढ़ाई के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को उज्जैन के स्वेज फार्म सक्षम आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के अवलोकन एवं हितलाभ वितरण कार्यक्रम में उक्त बातें कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण आहार सप्ताह के अंतर्गत लगाई गई पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन कर सराहना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त पक्के भवन, फर्नीचर, खिलौने, पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, प्रारंभिक शिक्षा सब कुछ एक ही छत के नीचे एक ही जगह उपलब्ध करवाया जा रहा है।

- **भगवान जगन्नाथ का उज्जैन से प्राचीन संबंध**– मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान जगन्नाथ का उज्जैन से हजारों साल पुराना संबंध रहा है। उज्जैन के राजा इंद्रसेन ने वर्तमान ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बाबा जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया था। यहां पर गोपाल कृष्ण, भगवान बलराम और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित हैं। सनातन संस्कृति के 4 धामों में ओडिशा का जगन्नाथपुरी तीर्थस्थल भी विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पूर्व निर्धारित नई दिल्ली प्रवास के कारण उज्जैन की जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन में वे गुरुवार को शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन के कार्तिक चौक स्थित भगवान जगदीश मंदिर में पूजा कर दर्शन किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरी दुनिया में भारत का मान–सम्मान बढ़ा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार देश में हो रहे विकास के विशेष प्रयासों से कदम से कदम मिलाकर चल रही है।
- **मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बच्चों को झूला झुलाया**– मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र में लगे झूलों पर बच्चों को झुलाया। आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों ने नमस्ते सर कहकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिवादन कर गुलाब का फूल भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छोटे–छोटे बच्चों को दुलार करते हुए सभी को लड्डू के पैकेट, पोषण आहार के रूप में चना और मूंगफली के पैकेट वितरित किए।
- **हितलाभ वितरित किए**– मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंच से लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आश्वासन प्रमाण–पत्र एवं मातृ–वंदना योजना की पात्र महिलाओं को हितलाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने लाड़ली–लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिकाओं को दुलार कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

## कर्मचारियों को मिल रहा है पदोन्नति का लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशभर के शासकीय सेवकों को उनके हक में प्रमोशन का लाभ दिया जा रहा है, जो किसी कुंभ से कम नहीं है। हर दिन अलग–अलग विभागों के प्रमोशन की सूची आ रही है। राज्य सरकार ने तय किया है कि हर एक व्यक्ति, जो जहां है। उससे दक्षता और कठोरता से कार्य लेना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों के बेहतर जीवन की सभी आवश्यकताओं की चिंता भी सरकार का ही दायित्व है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन

के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता की सहभागिता वाले कार्यों से उत्साहवर्धन के साथ सरकार को नए काम करने का संकल्प मिलता है। इस दौरान प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल, महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रवि सोलंकी, श्री संजय अग्रवाल, संभागीय आयुक्त श्री आशिष सिंह, एडीजी श्री राकेश गुप्ता, डीआईजी श्री नवनीत भसीन, कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस कूमट, एडीएम श्री अत्येन्द्र सिंह गुर्जर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्रामीण महिलाएं एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया।

## सुप्रभात

निकले थे जो सहरा में कचनार खिलाने को
मशगूल है गुलशन में अब ख़ार उगाने को
अच्छे दिनों के नारे वे भूल ही चुके हैं
गुलशन को जो निकले थे गुलज़ार बनाने को
रोटी भी गरीबों को अब तो नहीं मयस्सर
दावा किया था जिनको जेवनार खिलाने को
है मात खा के पसरा अब नीम–सा सन्नाटा
हसरत से भरे थे वे दरबार सजाने को
छाई है वतन पर यों हर सिम्त दुख की चादर
सूरज जहाँ अड़ा था भिनसार उगाने को
हैं सिल्लियाँ सोने की अफसर के यहां निकलीं
आया था जो सेवक का किरदार निभाने को
यकसाँ नहीं है 'निश्चल' दुनिया–जहाँ की
हालत
चाहा था जिसे इक दिन हमवार बनाने को ।

**- ओम निश्चल**

# भारत के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर बड़ा साइबर खतरा!

### लीक हुईं हजारों फाइलें, रिपोर्ट में 'गंभीर खतरे' की चेतावनी

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में शामिल तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े हजारों संवेदनशील दस्तावेज कथित तौर पर लीक होने का मामला सामने आया है। रैनसमवेयर ग्रुप 'वर्ल्ड लीक्स' ने डार्क वेब पर दावा किया है कि उसने संयंत्र से जुड़े 19,000 से अधिक दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं।

इस घटनाक्रम ने देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा को लेकर नई

चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये दस्तावेज करीब 8.58 लाख फाइलों के उस बड़े डेटा सेट का हिस्सा हैं, जिसे कथित तौर पर परियोजना से जुड़े ठेकेदार रिलायंस ग्रुप से चुराया गया। रिलायंस ग्रुप ने मीडिया से बातचीत में तीसरे पक्ष के डेटा सेंटर प्रोवाइडर 'योटा' के सर्वर पर 'आंशिक डेटा उल्लंघन' की पुष्टि की।

- **विशेषज्ञों ने बताया गंभीर सुरक्षा जोखिम**– परमाणु सुरक्षा पर काम करने वाले संगठन न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के सीनियर डायरेक्टर निकोलस रोथ ने कहा कि यह डेटा लीक संयंत्र की सुरक्षा के लिए 'गंभीर जोखिम' पैदा कर सकता है। उनके मुताबिक, इन दस्तावेजों से यह जानकारी मिल सकती है कि परियोजना तक किसकी पहुंच है और वह पहुंच किन–किन सिस्टम तक जाती है, जिससे किसी संभावित हमलावर को रणनीतिक फायदा मिल सकता है।
- **ऑपरेशनल सिस्टम सुरक्षित, लेकिन खतरा बरकरार**– साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि संयंत्र के संचालन से जुड़े रिएक्टर सिस्टम से समझौता हुआ हो। इसके बावजूद लीक हुए दस्तावेज हमलावरों को परियोजना के सहयोगी नेटवर्क, सप्लायर चेन और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे में कमजोरियों का फायदा उठाने में मदद कर सकते हैं।

### दस्तावेजों में क्या-क्या होने का दावा

रॉयटर्स ने 2016 से लेकर 2025 के मध्य तक के दस्तावेजों की समीक्षा की, लेकिन उनकी प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सका। कथित रूप से लीक फाइलों में वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट, कॉमन कंट्रोल रूम के फ्लोर लेआउट, उपकरणों की निरीक्षण रिपोर्ट, सप्लायर सूची, वेंडर प्रस्ताव, बैठकों के रिकॉर्ड और बीमा से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।

### कैबिनेट में हुए 7 बड़े फैसले

# बनारस में गंगा किनारे बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, रेल अपग्रेड और सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 15 जुलाई को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मोबाइल फोन प्रोडक्शन तक कई बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर और रेलवे प्रोजेक्ट्स से जुड़े सात बड़े फैसले हैं। इस पैकेज में सेमीकॉन 2.0, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और यूरिया-2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी शामिल हैं, जिन पर कुल 2,19,353 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई। इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी गई।

प्रेस ब्रीफिंग केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा लिए गए सात बड़े फैसले पेश कर रहा हूं।

### डांगोआपोसी और राजखरसवां के बीच चौथी रेलवे लाइन

नई यूरिया नीति 2026 को मंजूरी मिलीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आज किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 'नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया-2026' को मंजूरी दी है। यह नीति देश में गैस आधारित यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की स्थापना के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देगी।

# मध्यप्रदेश में लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

**भोपाल (एजेंसी)।** मध्य प्रदेश सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्रॉफ्ट में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बेहद कड़े नियम प्रस्तावित किए गए हैं। नए मसौदे के मुताबिक, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए संबंधित जिले के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई जोड़ा बिना रजिस्ट्रेशन के लिव-इन में रहता है, तो उसे अधिकतम तीन महीने तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

माता-पिता को दी जाएगी जानकारी- इस प्रस्तावित कानून के तहत पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिव-इन में रहने वाले युवाओं के माता-पिता को उनके रिलेशनशिप स्टेटस की औपचारिक सूचना दी जाएगी। इसके अलावा, स्थानीय पुलिस थानों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पंजीकृत लिव-इन जोड़ों का पूरा रिकॉर्ड मेनटेन करना होगा। खास बात यह है कि मकान मालिक या पड़ोसी भी बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे लिव-इन रिलेशनशिप की शिकायत कर सकेंगे।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20°c | न्यूनतम 18°c

# सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 16 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

## पंजाब कांग्रेस में बगावत पर हाईकमान में मतभेद

● बघेल-राहुल की टीम वड़िंग पर अड़ी, खड़गे बदलाव पर चर्चा के पक्ष में बाजवा चन्नी से मिले ● प्रताप सिंह बाजवा प्रधान बन सकते हैं

**लुधियाना (एजेंसी)।** विधानसभा चुनाव से करीब 7 महीने पहले पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर हाईकमान में भी मतभेद हो गए हैं। कांग्रेस सोर्सेज के मुताबिक इस मामले में राहुल गांधी की टीम और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अलग-अलग राय है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल व पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल नहीं चाहते थे कि राजा वड़िंग को प्रधान की कुर्सी से हटाया जाए। वहीं खड़गे बदलाव को लेकर चर्चा करने के पक्ष में हैं। यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल से एक घंटे मीटिंग के बाद खड़गे ने भी बघेल को तलब कर पंजाब की स्थिति पर सवाल-जवाब किए।

## भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा सकता है अमेरिका

● रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी; संसद में बिल पेश, 5 देश निशाने पर

**वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)।** अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है। यह बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया जा रहा है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके।

## भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील लागू

● सस्ती हो गईं व्हिस्की, रम, वोडका, लग्जरी कारें और ब्यूटी प्रॉडक्ट्स

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** भारत और ब्रिटेन के बीच आज बुधवार 15 जुलाई 2026 से व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए ) लागू हो गया है। इस एग्रीमेंट के लागू होते ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का एक नया दौर भी शुरू हो गया है। इस समझौते से भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच मिलेगी। इसके साथ-साथ ब्रिटेन से भारत आने वाले कई प्रॉडक्ट पर उत्पाद शुक्ल भी चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा। इससे कृषि, उद्योग, सेवा सेक्टर, एमएसएमई और पेशेवरों को नए अवसर मिलने की संभावना है। इससे व्हिस्की, रम, वोडका, लग्जरी कारें और ब्यूटी प्रॉडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे।

### संक्षिप्त समाचार

## नोएडा में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग, 2 जिंदा जले

● नोएडा में सीढ़ियों के सहारे 50 परिवारों को बचाया

**नोएडा (एजेंसी)।** नोएडा में बुधवार सुबह 11 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए। एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए। फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियों के सहारे 50 परिवारों का रेस्क्यू किया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। इसी दौरान उसमें धमाका हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। 30 से 40 बाइकें जलकर राख हो गईं।

## दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया आगे बढ़ी, अंतिम सूची 19 अक्टूबर को

**नईदिल्ली(एजेंसी)।** दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। राजधानी में मतदाता सूची के एसआईआर अभियान के 15 दिन पूरे होने तक चुनाव आयोग घर-घर गणना फॉर्म पहुंचाने में लगभग लक्ष्य हासिल कर चुका है, लेकिन इन्हें ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज करने की रफ्तार अब भी धीमी है। हर आठ में सिर्फ एक फॉर्म ही डिजिटाइज हो पाया है।

## सीबीएसई डिजिटल मार्किंग सिस्टम

● सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की पीड़ा पर संज्ञान लिया

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के डिजिटल मार्किंग सिस्टम से विद्यार्थियों की 'निराशा' पर चिंता जताई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक पीआईएल में सहायता मांगी, जिसमें केंद्र सरकार और सीबीएसई से ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिये परीक्षा कराने के लिए नियम बनाने की अपील की गई है। यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के सामने आया। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से केस से निपटने में सहायता मांगते हुए कहा, छोटे बच्चों की निराशा देखिए।

## 'खतरे में सोनम वांगचुक की जान'

### जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कोर्ट से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करके सोनम वांगचुक को मेडिकल मदद मुहैया कराने की मांग की गई है।

## राजस्थान-एमपी में मानसून थमा

**यूपी-बिहार में भारी बारिश**

● बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का असर; ओडिशा में रेड अलर्ट

**नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर (एजेंसी)।** मानसून देशभर में एक जैसा काम नहीं कर रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में मानसून थम गया है। जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ट्रफ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पूर्वी भारत में आकर रुक गई हैं। इससे पश्चिम-उत्तर भारत तक पर्याप्त मात्रा में नम हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए बारिश कम हो रही है।

मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ दिनों बाद नया लो-प्रेशर सिस्टम बनने या मानसून ट्रफ के पश्चिम की ओर बढ़ने पर इन राज्यों में भी अच्छी बारिश शुरू हो सकती है।

### असम-अरुणाचल में बाढ़ से 1.40 लाख लोग प्रभावित

अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बाढ़, लैंडस्लाइड और भारी बारिश से चार जिलों में नुकसान हुआ। राज्य में 1.02 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, अब तक 7 लोगों की मौत और 29 घायल हुए हैं। वहीं, असम के 6 जिलों के 99 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 37,032 लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा असर लखीमपुर

ओडिशा में बारिश का रेड अलर्ट है।

सैटेलाइट इमेज में बारिश का पूरा फोकस पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ऊपर घने बादल हैं।

### ओडिशा में जगन्नाथ रथयात्रा से पहले रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने ओडिशा के कई इलाकों में रथ यात्रा के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें पुरी भी शामिल है। यह चेतावनी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र के कारण जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बांग्लादेश के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम में हो रहे इस बदलाव के कारण बुधवार से शुक्रवार सुबह तक पुरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है।

## राममंदिर चढ़ावा चोरी-2 आरोपियों को जेल से ले गई पुलिस

● पूछेगी- पैसा कैसे चुराया, कहां छिपाया? सीईओ के लिए 24 घंटे में 1000 आवेदन

**अयोध्या (एजेंसी)।** अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा और रिटायर्ड बैंककर्मी सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने 14 घंटे की रिमांड पर लिया है। बुधवार सुबह 8 बजे पुलिस फैजाबाद जेल पहुंची और दोनों को पुलिस लाइन ले गई। पूछताछ के बाद आरोपियों को उनके घर भी ले जाया जा सकता है।पुलिस पता लगाएगी कि आरोपियों ने चढ़ावे के पैसे कैसे चुराए, उन्हें कहां छिपाया? रमाशंकर के पास चढ़ावे को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पुलिस को उसके बैंक खाते में 7.32 लाख रुपए मिले हैं। सुभाष चढ़ावा गिनने वालों की निगरानी करते थे। एसबीआई के रिटायर कर्मचारी हैं।

14 जुलाई (मंगलवार) को पुलिस ने रमाशंकर और सुभाष श्रीवास्तव को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 14 घंटे की रिमांड मंजूर की थी। इससे पहले, पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय को 40 घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है।

## यूपी-बिहार में भारी बारिश, गया में स्टूडेंट्स पर बिजली गिरी

**नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर (एजेंसी)।** मानसून देशभर में एक जैसा काम नहीं कर रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में मानसून थम गया है। जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है।

बिहार के गयाजी में बुधवार को स्कूल जा रहे तीन बच्चों पर बिजली गिर गई। एक बच्चे की मौत हो गई। समस्तीपुर में भी दो बिजली की चपेट में आने से महिला समेत दो की मौत हो गई।

मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ट्रफ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पूर्वी भारत में आकर रुक गई हैं। इससे पश्चिम-उत्तर भारत तक पर्याप्त मात्रा में नम हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए बारिश कम हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ दिनों बाद नया लो-प्रेशर सिस्टम बनने या मानसून ट्रफ के पश्चिम की ओर बढ़ने पर इन राज्यों में भी अच्छी बारिश शुरू हो सकती है।

## मप्र में लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

● नहीं कराया तो 3 महीने की जेल, यूसीसी ड्राफ्ट में कड़े प्रावधान

**भोपाल (एजेंसी)।** मध्य प्रदेश सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्रॉफ्ट में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बेहद कड़े नियम प्रस्तावित किए गए हैं। नए मसौदे के मुताबिक, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए संबंधित जिले के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई जोड़ा बिना रजिस्ट्रेशन के लिव-इन में रहता है, तो उसे अधिकतम तीन महीने तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

**माता-पिता को दी जाएगी जानकारी-** इस प्रस्तावित कानून के तहत पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिव-इन में रहने वाले युवाओं के माता-पिता को उनके रिलेशनशिप स्टेटस की औपचारिक सूचना दी जाएगी। इसके अलावा, स्थानीय पुलिस थानों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पंजीकृत लिव-इन जोड़ों का पूरा रिकॉर्ड मेनटेन करना होगा। खास बात यह है कि मकान मालिक या पड़ोसी भी बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे लिव-इन रिलेशनशिप की शिकायत कर सकेंगे।

### ममता बनर्जी को एक और झटका, टीएमसी विधायक मदन मित्रा बागी गुट में शामिल

**कोलकाता (एजेंसी)।** टीएमसी विधायक मदन मित्रा बुधवार को विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के बागी खेमे में शामिल हो गए. मदन को पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। मदन मित्रा जाने के साथ ही पार्टी के अंदर चल रही अनबन और गहरी हो गई है।

## पुरी रथयात्रा आज से शुरु

**पुरी (एजेंसी)।** ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा 16 जुलाई, गुरुवार से शुरू होगी। यह भव्य उत्सव 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। रथयात्रा को लेकर पुरी के होटल और लॉज पूरी तरह फुल हो चुके हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक, इस साल फरवरी से ही बुकिंग शुरू हो गई थी।

### यूपी के युवाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा

#### अब हर जिले में बनेगा स्किल-इंडस्ट्रियल जोन; ऑन डिमांड मिलेगी ट्रेनिंग

**लखनऊ(एजेंसी)।** विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा कार्यशक्ति है और इसे अवसर देकर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बनाया जा रहा है। हर जिले में एमएसएमई, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और श्रम एवं सेवायोजन विभाग के समन्वय से स्किल-इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे।

### महानगरों के खौफनाक आंकड़े...

## जलवायु परिवर्तन खामोशी से छीन रहा है आपकी नींद

● दिल्लीवालों के लिए रेड अलर्ट, सालाना 66.8 घंटे की नींद कम हो रही

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** देश की राजधानी में रहने वाले लोगों की सेहत पर अब मौसम की सीधी मार पड़ने लगी है। एक हालिया रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार, बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण दिल्ली का हर नागरिक सालाना औसतन 66.8 घंटे की नींद खो रहा है। इसमें से पांच घंटे की नींद सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़े तापमान की वजह से कम हुई है। यूं तो देश के अन्य बड़े महानगरों की तुलना में दिल्ली में नींद का यह नुकसान सबसे कम दर्ज किया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि साल भर में करीब 67 घंटे की नींद कम होना दिल्लीवालों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा रेड सिग्नल है।

● **दिल्ली में नींद उड़ने की बड़ी वजह, 'अर्बन हीट आइलैंड'-** दिल्ली जैसी घनी आबादी वाले महानगरों में कंक्रीट के ढांचे, गाड़ियों का धुआं और हरियाली की कमी मिलकर 'अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट' पैदा करते हैं। इसके कारण सूरज ढलने के बाद भी कंक्रीट की इमारतें और सड़कें गर्मी को रोके रखती हैं, जिससे रात का तापमान सामान्य से काफी अधिक बना रहता है। दिल्ली में गर्मी के कारण होने वाले कुल स्लीप लास में से 7 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज का नतीजा है।

### ● देश के अन्य महानगरों से तुलना: कहां कितनी उड़ रही है नींद?

भले ही दिल्ली इस सूची में सबसे नीचे है, लेकिन चेन्नई और मुंबई जैसे तटीय शहरों में उमस और गर्मी ने रातों की नींद पूरी तरह हराम कर रखी है। देश के प्रमुख शहरों में गर्मी से उड़ती नींद (सालाना आंकड़े)

| शहर | गायब हुई नींद | परिवर्तन का असर |
|---|---|---|
| चेन्नई | 93 घंटे | 5 घंटे |
| मुंबई | 84 घंटे | 5 घंटे |
| कोलकाता | 80 घंटे | 5 घंटे |
| अहमदाबाद | 78 घंटे | 6 घंटे |
| हैदराबाद | 75 घंटे | 7 घंटे |
| बेंगलुरु | 67 घंटे | 8 घंटे (ज़्यादा असर) |
| दिल्ली | 66 घंटे (सबसे कम नुकसान) | 5 घंटे |
| पुणे | 65 घंटे | 6 घंटे |

**सबसे बुरा हाल** - चेन्नई के लोगों का है, जहां हर व्यक्ति साल में 93 घंटे की नींद खो रहा है

**दिल्ली की स्थिति** - दिल्ली इस सूची में सबसे नीचे है, लेकिन यहां भी लोग हर साल करीब 66 घंटे कम सो पा रहे हैं, जिसमें से 5 घंटे का नुकसान सीधे तौर बेंगलुरु भले ही ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां क्लाइमेट चेंज का असर (12 प्रतिशत) सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।

### ● सेहत पर पड़ रहा है भारी असर

डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के अनुसार, नींद की यह लगातार हो रही कमी कोई आम बात नहीं है। इसके कारण लोगों में कई गंभीर बीमारियां पनप रही हैं।

**मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन-** नींद पूरी न होने से मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है और अवसाद का खतरा बढ़ता है।

**गंभीर बीमारियां-** कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, दिल से जुड़ी बीमारियां और याददाश्त में कमी।

# सांसद भारत सिंह कुशवाह दतिया उपचुनाव के प्रभारी

- **राहुल कोठारी को बीजेपी ने सह प्रभारी बनाया**

**भोपाल (नप्र)।** दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह को प्रभारी बनाया है। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के करीबी और भाजपा के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को दतिया उप चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।

### दतिया में 30 जुलाई को मतदान

दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है दतिया में भाजपा ने पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस से पूर्व विधायक घनश्याम सिंह और आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव चुनाव लड़ रहे हैं।

# जनजातीय कार्य विभाग में होंगे हजारों शिक्षकों के प्रमोशन

## उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक के पदों पर मिलेगी पदोन्नति

**भोपाल (नप्र)।** हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति के नए नियमों पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में सहकारिता विभाग ने पदोन्नति नियम-2025 के तहत 15 संवर्गों में कुल 613 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। वहीं, जनजातीय कार्य विभाग ने भी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है। विभाग जल्द ही 400 उच्च माध्यमिक शिक्षकों और करीब 11 हजार माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी करेगा।
सहकारिता विभाग में 613 अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रथम श्रेणी के 41, द्वितीय श्रेणी के 84, तृतीय श्रेणी के 486 तथा चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।
इनमें प्रमुख रूप से संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के 22, उप आयुक्त एवं उप पंजीयक के 19, सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक के 13, अंकेक्षण अधिकारी के 71, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के 196, सहकारी निरीक्षक के 106, सहायक ग्रेड-2 के 111, सहायक ग्रेड-1 के 29, सहायक ग्रेड-3 के 26 सहित अन्य संवर्गों में पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं।

# करोड़ों की संपत्ति हड़पने बनवाया दानपत्र, फिर गोली मार दी

## भोपाल में रिटायर्ड दंपत्ति की हत्या मामले में दो प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार, दोनों सगे भाई

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल पुलिस ने सुदामा नगर कॉलोनी में रहने वाले दंपती हेमंत फिलेमोन और शकुंतला बारीक फिलेमोन की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। वारदात के करीब 20 दिन बाद पुलिस ने दो प्रॉपर्टी डीलरों- श्रीकांत चिंचलिया (40) और शशिकांत चिंचलिया (35) को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे भाई हैं। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि आरोपियों ने पहले धोखाधड़ी कर दंपती के मकान का दानपत्र (गिफ्ट डीड) अपने नाम कराया। फिर पूरी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए दोनों की हत्या

हेमंत बारीक
रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी

शकुंतला बारीक
रिटायर्ड नर्स

की साजिश रच दी। इससे पहले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने करीब 20 पुलिस टीमों के साथ मामले की पड़ताल की। 1500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई। मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन, डिजिटल और अन्य वैज्ञानिक सबूत जुटाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। 26 जून को दंपती के शव घर के भीतर सड़ी-गली हालत में मिले थे।

**आरोपियों ने इटारसी में दंपती का एक प्लॉट बिकवाया था-** पुलिस कमिश्नर ने बताया कि श्रीकांत और शशिकांत चिंचलिया लंबे समय से इस बुजुर्ग दंपती के बेहद करीबी और विश्वासपात्र बने हुए थे। वे उनकी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त का काम देखते थे। कुछ समय पहले दोनों ने इटारसी में दंपती का एक प्लॉट बिकवाया था। आरोप है कि इसी दौरान दस्तावेज तैयार करते समय आरोपियों ने चालाकी से दानपत्र तैयार करा लिया। इस दानपत्र में लिखा था कि दंपती की मृत्यु के बाद उनकी सुदामा नगर स्थित करोड़ों की संपत्ति इन दोनों आरोपियों के नाम दान कर दी जाएगी।

**मकान बिकता देख बदली रणनीति, गोली मारकर हत्या की साजिश रची-** आरोपियों को उम्मीद थी कि दंपती की स्वाभाविक या वक्त के साथ होने वाली मौत के बाद करोड़ों का मकान उनका हो जाएगा, लेकिन हाल ही में खेल बिगड़ गया। बुजुर्ग दंपती ने अचानक अपना सुदामा नगर वाला मकान बेचने का फैसला कर लिया और इसका सौदा भी लगभग तय हो गया था।

# 100 करोड़ से संवर रहा छोला स्थित खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर

## मंत्री सारंग बोले- मार्बल एवं प्राचीन नागर शैली दिखेगी, किया निरीक्षण

**भोपाल (नप्र)।** राजधानी भोपाल के छोला स्थित प्राचीन एवं प्रसिद्ध श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर परिसर में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का सहकारिता, मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने नगर निगम एवं संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए परियोजना को तय समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों से कहा कि कॉरिडोर निर्माण का मूल उद्देश्य श्रद्धालुओं को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि पुराने गर्भगृह की मूल संरचना और धार्मिक स्वरूप को पूरी तरह यथावत रखते हुए मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्र का विस्तार किया जाए, जिससे मंदिर की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक पहचान सुरक्षित रहे।

मंत्री श्री सारंग ने निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि परियोजना के सभी चरणों के लिए सुव्यवस्थित ड्राइंग एवं चरणबद्ध एक्शन प्लान तैयार किया जाए, जिससे निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में व्यवस्थित रूप से पूरा हो सके। साथ ही

निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश भी दिए।

**दर्शनार्थियों की सुविधा और न्यूनतम विस्थापन पर विशेष जोर-** मंत्री श्री सारंग ने कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान श्रद्धालुओं, स्थानीय रहवासियों एवं व्यापारियों को किसी प्रकार की अनावश्यक असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों के क्रियान्वयन में न्यूनतम विस्थापन सुनिश्चित किया जाए तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते की जाएं।

**नागर शैली में विकसित होगा भव्य हनुमान लोक-** मंत्री श्री सारंग ने बताया कि लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहे इस कॉरिडोर का निर्माण राजस्थान के व्हाइट मार्बल एवं प्राचीन नागर शैली की वास्तुकला के अनुरूप किया जा रहा है। मंदिर परिसर में सुंदरकांड की झलक प्रस्तुत करने वाला भव्य कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त होगा।

**आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा परिसर-** परियोजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था, भव्य कॉरिडोर, दर्शक दीर्घा, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अधोसंरचना, आधुनिक पार्किंग, चौड़ी सड़कें तथा अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। साथ ही दशहरा मैदान के खुले स्वरूप को संरक्षित रखते हुए वहां सार्वजनिक आयोजनों के लिए आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।

### भोपाल की नई सांस्कृतिक पहचान बनेगा हनुमान लोक

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिक विकास का संगम है। यह परियोजना विरासत भी और विकास भी की सोच को साकार करते हुए भोपाल की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी तथा भविष्य में धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर राजधानी भोपाल की नई पहचान के रूप में स्थापित होगा।

### उप मुख्यमंत्री ने रेडक्रास की आधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण यूनिट का किया लोकार्पण

# रीवा कृत्रिम अंग निर्माण का बनेगा केन्द्र

**भोपाल।** उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने भारतीय रेडक्रास समिति में आधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण यूनिट का रीवा में लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने ब्लड सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण करने के साथ तीन दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रेडक्रास समिति ने सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके रीवा का नाम रोशन किया है। समिति में कृत्रिम अंग निर्माण की आधुनिकतम उपकरणों से सज्जित कम्प्यूटराइज्ड यूनिट का शुभारंभ किया गया है। इससे अस्थि बाधित दिव्यांगजनों को सटीक नाप के कृत्रिम अंग प्राप्त होंगे। इस यूनिट से रीवा संभाग ही नहीं सागर संभाग, जबलपुर संभाग तथा पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश के समीपवर्ती जिलों के दिव्यांगों को भी कृत्रिम अंग की सुविधा मिलेगी। जिस कार्य के लिए दिव्यांगों दिल्ली, मुम्बई, जयपुर जैसे शहरों को जाना पड़ता था वह सुविधा अब रीवा शहर में उपलब्ध हो गई है। दिव्यांगों के कल्याण के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए समिति के चेयरमैन डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक अंग निर्माण यूनिट से रीवा कृत्रिम अंग निर्माण का केन्द्र बनेगा। रेडक्रास समिति ने गरीबों और पीड़ितों की सेवा में सदैव उत्कृष्ट कार्य किया है। कोरोना के संकटकाल में समिति के सदस्यों ने समाजसेवियों के साथ मिलकर जान हथेली में रखकर गरीबों को घर-घर जाकर निःशुल्क अनाज का वितरण किया था। समिति में ब्लड सेपरेशन यूनिट का भी लोकार्पण किया गया है। इस सुविधा से एक यूनिट रक्त का उपयोग तीन रोगियों की जान बचाने में किया जा सकता है। समारोह में रेडक्रास समिति के चेयरमैन डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी ने कहा कि समिति पीड़ितों की सेवा के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

# बदलाव के लिए भाकपा द्वारा आन्दोलन की तैयारी

**भोपाल।** केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जन विरोधी, फासीवादी नीतियों के खिलाफ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बदलाव जरूरी है के आव्हान के तहत आगामी महीनों में विभिन्न आन्दोलन किए जायेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने बताया कि भाकपा की विगत दिनों भोपाल में आयोजित राज्य परिषद की बैठक में तत्संबंधी निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनता पर अनावश्यक रूप से सामान नागरिक संहिता थोपने के खिलाफ विधान सभा सत्र के दौरान 21 जुलाई को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सभी जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर समान नागरिक संहिता को लागू नहीं करने की मांग की जाएगी।जनता की विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा द्वारा 6 अगस्त से 15 अगस्त तक देश व्यापी आव्हान के तहत मध्य प्रदेश में पद यात्राएं निकली जाएंगी। 1 सितम्बर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में बदलाव जरूरी है के आव्हान को लेकर विशाल आमसभा होगी।भाकपा को वैचारिक तथा सांगठनिक स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए सितम्बर से पार्टी क्लास आयोजित की जाएंगी । भाकपा द्वारा इस वर्ष कॉमरेड महेन्द्र वाजपेई जन्म शताब्दी समारोह और ज्योति बा फुले द्विशताब्दी समारोह के आयोजन भी किए जाएंगे।

# मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में 11 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित

### भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में तेजी से जारी है स्मार्ट मीटर स्थापना

**भोपाल।** मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को आधुनिक, पारदर्शी एवं डिजिटल विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में स्मार्ट मीटर स्थापना का कार्य निरंतर किया जा रहा है। अब तक 11 लाख 42 हजार 773 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि वृत्तवार स्मार्ट मीटर स्थापना में भोपाल शहर वृत्त में 4,69,964, सीहोर में 84,473, विदिशा में 80,633, ग्वालियर शहर में 79,071, नर्मदापुरम में 75,704, रायसेन में 50,502, बैतूल में 45,840, भोपाल (ओ एंड एम) में 45,670, गुना में 28,202, शिवपुरी में 28,528, राजगढ़ में 27,210, हरदा में 26,514, भिंड में 24,586, ग्वालियर (ओ एंड एम) में 22,389, मुरैना में 19,449, दतिया में 17,137, अशोकनगर में 9,265 तथा श्योपुर में 7,636 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।

स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को सटीक एवं पारदर्शी बिलिंग, बिजली खपत की रियल-टाइम जानकारी, ऑनलाइन मॉनिटरिंग तथा बेहतर उपभोक्ता सेवाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही बिजली वितरण प्रणाली को अधिक सक्षम, पारदर्शी एवं डिजिटल बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

### उपभोक्ताओं को घरेलू स्मार्ट मीटर से मिलने वाले फायदे

- ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है।
- बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती।
- ऐप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं।
- ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि ऊर्जा की खपत को बेहतर बना सकते हैं।
- ऊर्जा की खपत को ऑनलाइन ट्रैक करने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है।

# भोपाल के जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट मीटिंग 19 जुलाई को

### सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे; एसीएस, कमिश्नर-कलेक्टर ने निरीक्षण किया

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल के जगदीशपुर में 19 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग होगी। इसके चलते यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। बुधवार को अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला, भोपाल कमिश्नर कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने निरीक्षण किया।

कैबिनेट में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह विधेयक एक देश-एक विधान-एक प्रधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

**रानी महल और चमन महल का निरीक्षण-** ई-कैबिनेट बैठक की तैयारियों को लेकर अपर मुख्य सचिव शुक्ला ने जगदीशपुर पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। शुक्ला ने स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक बैठक के महत्व को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी तरह चाक-चौबंद और त्रुटिहीन होनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव शुक्ला ने जगदीशपुर पैलेस परिसर स्थित ऐतिहासिक रानी महल एवं चमन महल का अवलोकन किया। उन्होंने वहां बैठक व्यवस्था, सुरक्षा मानकों, सौंदर्यीकरण और ई-कैबिनेट के लिए आवश्यक आधुनिक तकनीकी प्रबंधों को देखा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप दायित्वों का निर्वहन करें और प्रत्येक विभाग अपने सौंपे गए कार्यों को पूरी तत्परता से प्रबंधित करें। जिससे सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

# युवा कौशल दिवस पर एसजीएसयू एवं आईसेक्ट इंडिया ने मनाया

### 'कौशल चर्चा 2026' का सातवां संस्करण

**भोपाल।** विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी (एसजीएसयू) एवं आईसेक्ट इंडिया द्वारा आयोजित 'कौशल चर्चा 2026' के सातवें संस्करण का मुख्य आयोजन मंगलवार को उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुआ। 13 से 16 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे इस कौशल महोत्सव में विद्यार्थियों, उद्योग विशेषज्ञों, स्किल चैंपियंस, प्रशिक्षकों एवं शिक्षाविदों ने भविष्य के कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर व्यापक विचार-विमर्श कर रहे हैं।

कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष की विश्व युवा कौशल दिवस की थीम 'Skills for a Shared Future' के अनुरूप किया गया। उद्घाटन सत्र में स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी, कुलगुरु डॉ. विजय सिंह एवं कुलसचिव डॉ. सितेश कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं आईआईएसएम के संस्थापक निदेशक नीलेश कुलकर्णी, रोरिंग माइंड्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीश आर. नायर तथा ऑल्टेरा कलेक्टिव के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम छाबरिया ने विशेष वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित किया।अपने स्वागत उद्बोधन में डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि आज केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं को कौशल, उद्योग अनुभव, वैश्विक प्रमाणन और निरंतर सीखने की संस्कृति अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और उभरते उद्योगों के दौर में स्किल सर्टिफिकेशन, मजबूत रिज्यूमे और व्यावहारिक अनुभव युवाओं की सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। उन्होंने एसजीएसयू द्वारा उद्योग-समेकित शिक्षा, एआई आधारित शिक्षण, वैश्विक प्रमाणन और रोजगारोन्मुखी कौशल विकास की विभिन्न पहलों की भी जानकारी दी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीलेश कुलकर्णी ने खेल क्षेत्र में उभरते करियर अवसरों और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस एवं खेल कौशल के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं प्रतीश आर. नायर ने युवाओं से निर्भीक होकर नए अवसरों को अपनाने, प्रभावी नेटवर्किंग विकसित करने और स्वयं को लगातार बेहतर बनाने का आह्वान किया।

संपादकीय

# शाबाश बेटियों!

इंग्लैंड में भारतीय टी 20 पुरूष टीम ने भले ही बेहद निराश किया हो, लेकिन क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों टेस्ट मैच में जो कमाल किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए, कम है। इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारत की बेटियों ने क्रिकेट के 142 साल के इतिहास में नया रिकॉर्ड रच डाला। लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए पहले वीमेंस टेस्ट क्रिकेट मैच को भारतीय टीम ने न केवल 270 रनों से जीता बल्कि बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और मप्र की क्रांति गौड़ ने वहां के 'हॉल ऑफ फेम' में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करवा लिया। इंग्लैंड की टीम को मैच के चौथे और अंतिम दिन दूसरी पारी में जीत के लिए 457 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन उसकी पूरी टीम दूसरी पारी में 186 रनों पर ऑलआउट हो गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है, क्योंकि इंग्लैंड में ही खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप मैच में भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। लॉर्ड्स पर खेले गए इकलौते टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस मैच को कई उपलब्धियों के लिए भी याद किया जाएगा। इसी मैदान पर 142 साल पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। उसके बाद यहां महिला टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच खेला गया। इस टेस्ट मैच में यास्तिका भाटिया ने शतकीय पारी खेली तो क्रांति गौड़ ने पांच विकेट लिए। इसके पहले इंग्लैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया था जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। इस दौरान स्मृति मंधाना ने 83 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए इंग्लैंड की टीम को 170 रनों पर ऑलआउट कर दिया और 115 रनों की बढ़त बनाई। मध्यम गति की तेज़ गेंदबाज़ क्रांति गौड़ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट मैच में पांच विकेट लेने वालीं पहली गेंदबाज़ बन गई हैं। दूसरी पारी में भारतीय टीम के बल्लेबाज़ों ने शानदार खेल दिखाया और विकेटकीपर बल्लेबाज़ यास्तिका भाटिया ने शतकीय पारी खेली। इसी के साथ ही यास्तिका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर शतक लगाने वालीं पहली महिला बल्लेबाज़ बन गई हैं। यास्तिका ने 113 रन बनाए और इस दौरान 14 चौके भी लगाए। इस शानदार मैच को देखने महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी लॉर्ड्स पहुंचे थे और वो विजेता महिला खिलाड़ियों से भी मिले। यह जीत न केवल भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हमारी बेटियों में क्या क्षमता है। इस मैच में जीत के साथ ही उन्होंने साबित किया कि वे विश्व क्रिकेट में एक मजबूत शक्ति हैं। इस जीत के पीछे कई कारक हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है टीम की एकजुटता और सामूहिक प्रयास। भारतीय महिला टीम ने अपनी शानदार फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ एक मजबूत जीत हासिल करने में मदद मिली। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तान ने अपनी रणनीति और नेतृत्व क्षमता का भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। महिला खिलाड़ियों के इस शानदार खेल से क्रिकेट प्रेमियों में उनके खेल प्रदर्शन को लेकर रूचि जागी है। हालांकि पिछले दिनो टी 20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमी फाइनल में पहुंचने से चूक गई थी, लेकिन उसका टीम के खेल प्रदर्शन पर असर नहीं पड़ा, यह अच्छीश बात है। इस टीम से आगे भी देश को बहुत उम्मीदें रहेंगीं।

नजरिया

# भारत के पास है विकास के विनाश का विकल्प

निलेश देसाई
लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं।

बड़े बांधों का विस्थापन, कॉर्पोरेट खेती का संकट और अंधी पूंजीवादी दौड़–इन सबके बीच जेरेमी लेंट की 'इको-सभ्यता' और गांधी का 'ग्राम स्वराज' मिलकर एक ऐसा विकास मॉडल प्रस्तुत करते हैं, जो मनुष्य, समाज और प्रकृति तीनों के साथ न्याय करता है। भारत में विकास की कहानी पिछले सात दशकों से लगभग एक जैसी सुनाई जाती रही है। कहा गया कि बड़े बांध बनेंगे तो बिजली आएगी, बड़े उद्योग लगेंगे तो रोजगार मिलेगा, आधुनिक बीज और रासायनिक खेती अपनाई जाएगी तो कृषि समृद्ध होगी। विकास की इस परिभाषा ने देश की अर्थव्यवस्था को गति तो दी, लेकिन एक प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है–इस विकास की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई?

उत्तर स्पष्ट है–आदिवासियों ने, छोटे किसानों ने, जंगलों ने, नदियों ने और प्रकृति ने। लाखों लोग अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति से विस्थापित हुए। किसान उत्पादन तो बढ़ाता गया, लेकिन उसकी आय घटती गई। मिट्टी की उर्वरता कम हुई, जलस्रोत सूखे और जैव विविधता लगातार नष्ट होती गई। आज जब जलवायु परिवर्तन, जल संकट और कृषि संकट एक साथ हमारे सामने खड़े हैं, तब यह पूछना आवश्यक हो गया है कि क्या विकास का यही एकमात्र रास्ता है?

इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं अमेरिकी चिंतक जेरेमी लेंट अपनी नई पुस्तक 'इको सिविलाइजेशनः मेकिंग ए वर्ल्ड देट वर्क्स फॉर ऑल' में। उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था स्वयं संकट का कारण है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस विकल्प की तलाश आज दुनिया कर रही है, उसके बीज भारत के गांधीवादी दर्शन में पहले से मौजूद हैं।

दुनिया में लंबे समय तक एक विचार हावी रहा कि पूंजीवादी विकास मॉडल का कोई विकल्प नहीं है। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर ने इसे एक नारे में बदल दिया था, 'देयर इज नो अल्टरनेटिव'। लेकिन आज जलवायु संकट, बढ़ती आर्थिक असमानता और सामाजिक विघटन ने इस नारे को खोखला साबित कर दिया है। विकल्प है, और वह विकल्प है- प्रकृति के साथ संतुलन, स्थानीय स्वायत्तता और सामुदायिक अर्थव्यवस्था पर आधारित विकास।

'वेल्थ पंप'–समृद्धि नहीं, संपत्ति का केंद्रीकरण

जेरेमी लेंट वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को 'वेल्थ पंप' अर्थात् 'संपत्ति खींचने वाली मशीन' कहते हैं। यह व्यवस्था तीन स्तरों पर लगातार काम करती है। पहला, यह प्रकृति से उसकी पुनर्जीवन क्षमता से अधिक संसाधन निकालती है। दूसरा, यह श्रम का अधिकतम शोषण करती है। तीसरा, यह पैदा हुई संपत्ति को समाज के सबसे ऊपर बैठे सीमित वर्ग के हाथों में केंद्रित कर देती है।

यदि भारत की स्थिति देखें तो यह विश्लेषण बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है। बड़े बांधों ने बिजली तो पैदा की, लेकिन लाखों लोगों को उनकी जमीन और संस्कृति से बेदखल कर दिया। खनन परियोजनाओं ने जंगलों को नष्ट किया, जबकि उनका लाभ स्थानीय समुदायों के बजाय बड़ी कंपनियों तक पहुंचा। कृषि में संकर बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर बढ़ती निर्भरता ने किसानों को आत्मनिर्भर उत्पादक से बाजार पर निर्भर उपभोक्ता बना दिया। किसान अब अपना बीज स्वयं नहीं बचाता, बल्कि हर वर्ष उसे खरीदने के लिए मजबूर होता है। मिट्टी कमजोर होती जाती है, लागत बढ़ती जाती है और किसान कर्ज के जाल में फंसता जाता है। यह केवल आर्थिक संकट नहीं है; यह सभ्यता का संकट है।

## प्रकृति हमें क्या सिखाती है?

लेंट कहते हैं कि यदि हमें टिकाऊ समाज बनाना है तो हमें प्रकृति से सीखना होगा। प्रकृति का कोई केंद्रीय नियंत्रक नहीं होता। जंगल में कोई सीईओ नहीं बैठा होता। फिर भी करोड़ों जीव, हजारों प्रजातियां और अनगिनत पारिस्थितिक प्रक्रियाएं अद्भुत संतुलन के साथ चलती रहती हैं। वहां सहयोग है, अंतर्निर्भरता है, विविधता है और संसाधनों का चक्रीय उपयोग है।

प्रकृति का नियम प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग पर आधारित है। यदि मानव समाज भी इसी सिद्धांत को अपनाए, तो विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन दोनों सुनिश्चित होंगे।

## गांधी का ग्राम स्वराजः भविष्य का विकास मॉडल

गांधी जी ने लगभग एक शताब्दी पहले जिस ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, वह आज पहले से अधिक प्रासंगिक दिखाई देती है। ग्राम स्वराज का अर्थ केवल पंचायत चुनाव नहीं था। इसका अर्थ था–आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। गांव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे। स्थानीय संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय समुदाय का हो। उत्पादन का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं बल्कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

इसी सोच को गांधी ने एक वाक्य में व्यक्त किया था- 'प्रोडक्शन बाय द मासेस, नॉट फॉर मॉस प्रोडक्शन।' अर्थात् उत्पादन अधिक से अधिक लोगों के हाथों में होना चाहिए, न कि उत्पादन कुछ विशाल कारखानों में केंद्रित हो जाए। आज सार्वजनिक नीति की भाषा में इसे सब्सिडरिटी प्रिंसिपल कहा जाता है- जो निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जा सकते हैं, उन्हें ऊपर की सरकारों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। गांधी ने यही बात दशकों पहले व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत की थी।

यदि भारत वास्तव में एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास मॉडल अपनाना चाहता है, तो तीन बड़े परिवर्तन आवश्यक हैं।

## 1. कॉर्पोरेट कृषि से पुनर्जीवनकारी खेती की ओर

नीति का केंद्र उत्पादन बढ़ाने से हटकर मिट्टी के स्वास्थ्य, जल संरक्षण, जैव विविधता और किसानों की आत्मनिर्भरता पर होना चाहिए।

स्थानीय बीज, सामुदायिक बीज बैंक, प्राकृतिक खेती, मिश्रित कृषि और स्थानीय बाजार केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि किसानों की लागत भी घटाते हैं और खाद्य संप्रभुता को मजबूत करते हैं।

## 2. बड़े बांधों की जगह स्थानीय जल प्रबंधन

जल संकट का समाधान केवल विशाल परियोजनाओं में नहीं है।

छोटे तालाब, चेक डैम, खेत तालाब, जलग्रहण विकास और सामुदायिक जल संरचनाएं कम लागत में अधिक टिकाऊ परिणाम देती हैं। इनसे न केवल भूजल पुनर्भरण होता है, बल्कि विस्थापन भी नहीं होता और जल पर समुदाय का नियंत्रण बना रहता है।

राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों ने यह सिद्ध किया है कि समुदाय आधारित जल प्रबंधन बड़े बांधों की तुलना में कहीं अधिक स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है।

## 3. निजीकरण नहीं, सामुदायिक स्वामित्व

पानी, जंगल, चरागाह, बीज और ऊर्जा जैसे बुनियादी संसाधनों को केवल बाजार की वस्तु नहीं बनाया जा सकता।

इन संसाधनों पर स्थानीय समुदायों का साझा अधिकार और प्रबंधन ही दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है। जब समुदाय मालिक बनता है, तब संरक्षण भी बढ़ता है और जवाबदेही भी।

## विकास का नया अर्थ

आज विकास को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से मापा जाता है। लेकिन यदि जीडीपी बढ़े और नदियां मर जाएं, जंगल खत्म हो जाएं, किसान आत्महत्या करें और समाज में असमानता बढ़ती जाए, तो क्या इसे विकास कहा जा सकता है? वास्तविक विकास वह है जिसमें प्रकृति की पूंजी घटे नहीं, सामाजिक विश्वास मजबूत हो और आर्थिक अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण हो। जेरेमी लेंट की इको-सभ्यता और गांधी का ग्राम स्वराज दोनों हमें यही बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है। विकास का उद्देश्य बाजार का विस्तार नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए।

आज पूरी दुनिया जलवायु संकट, जैव विविधता के क्षरण और बढ़ती आर्थिक असमानता से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत के सामने केवल चुनौती नहीं, बल्कि अवसर भी है। यदि भारत गांधी के ग्राम स्वराज, प्राकृतिक खेती, सामुदायिक जल प्रबंधन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकेंद्रीकृत शासन को आधुनिक विज्ञान और नई तकनीकों के साथ जोड़ सके, तो वह दुनिया के सामने विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। एक सीमित ग्रह पर असीमित उपभोग और अंतहीन आर्थिक वृद्धि का सपना अंततः विनाश की ओर ही ले जाएगा। अब समय आ गया है कि विकास की परिभाषा बदली जाए। असली प्रगति वह नहीं है जो कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ा दे। असली प्रगति वह है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए, नदियों को जीवित रखे, जंगलों को सुरक्षित रखे, किसानों को आत्मनिर्भर बनाए और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करे। शायद यही वह बिंदु है जहां गांधी का 'अंत्योदय' और जेरेमी लेंट की 'इको-सभ्यता' एक-दूसरे से मिलते हैं। और शायद यही वह रास्ता है, जो भारत को केवल विकसित राष्ट्र नहीं, बल्कि एक सभ्य और टिकाऊ राष्ट्र बना सकता है।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय

# सहकारिता के नए आकाश में नई उड़ान

डॉ. कन्हैया त्रिपाठी
लेखक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी एवं पंजाब केंद्रीय विशाविद्यालय में चेयर प्रोफ़ेसर है।

भारत का सहकारिता आन्दोलन अपने नए स्वरूप में आ गया है। बौद्धिक समाज का उत्पादन एवं उनसे राष्ट्र निर्माण की कोशिश भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वैसे तो आणंद का नाम श्वेत क्रांति के स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित है। जहां त्रिभुवनदास पटेल, सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रेरणा और डॉ. वर्गीज़ कुरियन की दूरदर्शिता व आत्मविश्वास अपना नया आकार पाया। इस भूमि पर जिन मनीषियों ने कार्य किया उन्होंने सिद्ध किया कि यदि उत्पादक स्वयं अपने संगठन के स्वामी बन जाएं, तो आर्थिक स्वतंत्रता किसी स्वप्न से कम नहीं होती। अमूल का उदहारण लें तो अमूल की सफलता केवल दुग्ध उत्पादन की कहानी नहीं है, यह विश्वास, सहभागिता और लोकतांत्रिक प्रबंधन की सफलगाथा है। इसी विरासत को नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाने का संकल्प है- त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जिसे अमित शाह वर्षों से स्थापित करना चाहते थे। विश्व में यह विश्वविद्यालय उस परिवर्तनकारी सोच का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें सहकारिता को केवल डेयरी, चीनी या बैंकिंग तक सीमित नहीं किया जाएगा अपितु सहकारिता का विस्तार जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, बीज उत्पादन, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं, ई-कॉमर्स, हरित ऊर्जा और ग्रामीण उद्यमिता को समेकित करते किया जाएगागढ़ेगा। इस विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रबंधन, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय अनुशासन और वैश्विक दृष्टि पर बहसें होंगी। प्रथम दीक्षांत समारोह हुआ तो जिन्हें नई डिग्रियां मिल रही हैं उससे यह पता चलता है कि यह विश्वविद्यालय भविष्य के सहकारी नेतृत्व को गढ़ने की कोशिश करने जा रहा है।

देश के उत्थान पॉलिसीज पर कार्य करने वाले चेंजमेकर यह मान रहे हैं कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय संभावनाओं का संस्थागत स्वरूप है। यहां से निकलने वाले विद्यार्थी केवल डिग्रीधारक नहीं लेकर निकालेंगे अपितु वे सहकारिता के नए राजदूत होंगे। वे गांवों में नई आशा की लौ जगाएंगे। किसानों को बाजार से जोड़ेंगे। महिलाओं को आर्थिक शक्ति देंगे। युवाओं को उद्यमिता की राह दिखाएंगे। समाज में साझेदारी की संस्कृति को सुदृढ़ करेंगे। उनका कार्य आर्थिक प्रगति और सामाजिक संवेदनाओं दोनों को निर्मित करेंगे।

इस विश्वविद्यालय के विजन प्लान को सही से पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि एनईपी-2020 के माध्यम से शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध करने हेतु नहीं निर्धारित हुए हैं अपितु वह व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए भी है और उसके लिए ठीक-ठीक कार्य आईआईएम जैसे संस्थाओं से अधिक सहक्रिता विश्वविद्यालय करेगा। भारतीय सहकारिता विश्वविद्यालय का इसी सत्य का आभास है। यह उस क्षण का आरंभ है जब विद्यार्थी पुस्तकों से बाहर निकलकर जीवन की खुली पाठशाला में प्रवेश कर रहे हैं। वास्तव में वास्तविक विश्वविद्यालय वही है जो वास्तविक जीवन मूल्य परिवर्तन का माध्यम बने। नए जीवन की शुरुआत प्रथम दीक्षांत समारोह से जो शुरू करने जा रहे हैं वे रिश्क में नहीं है अपितु वे सन्देश दे रहे हैं कि जीवन मूल्य भी अब सहकारिता से सुरक्षित होंगे। यह सहकारिता में नए आकाश में नई उड़ान है चाहे कोई माने या न माने। यह उड़ान निःसंदेह सहक्रिता एवं गृह मंत्री अमित शाह के संकल्पों से संभव हो पा रही है, ऐसा कहा जाए तो कोई अतिश्योक्तिपूर्ण बात न होगी।

हम सभी आज यह महसूस करने लगे हैं कि भारत की सहकारी व्यवस्था आज विश्व की सबसे बड़ी जनआधारित आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक है। करोड़ों नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहकारी संस्थाओं से जुड़े हैं। किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों, कारीगरों और ग्रामीण युवाओं के लिए सहकारिता केवल संस्था नहीं, बल्कि अवसर का द्वार है। लाभ और लोकहित के बीच संतुलन स्थापित कर नवाचार हेतु विकास का माध्यम सहकारिता बनने जा रही है। सहकारिता का प्राण उसके नैतिक मूल्यों में निहित है। विश्वास, पारदर्शिता, सहभागिता, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक निर्णय, ये वे आधार हैं जिन पर सहकारिता का विशाल भवन खड़ा हुआ है। यदि इन मूल्यों के साथ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय दायित्वबोध लेकर ऐसे चरित्रवान नेतृत्व का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। विशेष विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि यह विश्वविद्यालय सहकारिता के नए पक्षियों के कलरव से लोकमंगल का माध्यम बनने वाला है। जो 302 विद्यार्थी एवं 2 स्कॉलर को स्नातक एवं पीएचडी की उपाधि मिली है, यह तो एक शुरुआत है। केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने गुजरात के आणंद में 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में कहा भी कि नरेंद्र मोदी जी के च्सहकार से समृद्धिज्‍ के संकल्प तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्थापित 'त्रिभुवन' सहकारी यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है। यह यूनिवर्सिटी भविष्य के सहकारी नेतृत्वकर्ताओं, शोधकर्ताओं और पेशेवर प्रबंधकों को तैयार कर भारत के सहकारी आंदोलन को नई दिशा और नई गति प्रदान करेगी। यह बात शत-प्रतिशत सही भी है और उनके प्रयासों का एक तरह से अभिनंदन भी है।

सहकारिता को नया बौद्धिक आधार ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना से जो मिलने लगा है जिसने ज्ञान, शोध, नवाचार और मानवीय मूल्यों का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया है तो ऐसे ऐतिहासिक पहल को स्वर्णाक्षरों में अंकित भी किया जाना चाहिए और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की जानी चाहिए। दरअसल, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय उस विश्वास का प्रतीक अब बनने जा रहा है जो संगठित समाज की शक्ति व किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पहल है। भारत इससे विश्व की सहकारिता को टक्कर देगा और देश को सशक्त बनाएगा, इसे नहीं भूलना चाहिए। हमारी महिला डिग्रीधारितों की एक नई नवाचार की प्रयोगशाला होगी। महिलाएं सशक्तीकरण का नया अध्याय लिखेंगी, यह विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में शामिल होने जा रहा है। हम खुद विश्व जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ेंगे और सहकारिता के माध्यम से सशक्त बनकर और भारतीय जनमानस को सशक्त बनाकर सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ विकास का नया मार्ग तैयार करेंगे।

> हम सभी आज यह महसूस करने लगे हैं कि भारत की सहकारी व्यवस्था आज विश्व की सबसे बड़ी जनआधारित आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक है। करोड़ों नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहकारी संस्थाओं से जुड़े हैं। किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों, कारीगरों और ग्रामीण युवाओं के लिए सहकारिता केवल संस्था नहीं, बल्कि अवसर का द्वार है। लाभ और लोकहित के बीच संतुलन स्थापित कर नवाचार हेतु विकास का माध्यम सहकारिता बनने जा रही है।

सहकारिता विश्वविद्यालय के संबंध में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का पहला प्रमुख बयान 26 मार्च 2025 को लोकसभा में 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक' पर चर्चा के दौरान आया था। इसके बाद, 05 जुलाई 2025 को गुजरात के आणंद में इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में उन्होंने इसके उद्देश्यों को विस्तार से रखा तो इसके बारे में जो भी कल्पनाएँ लोग किए हों लेकिन अब तो इस विश्वविद्यालय से सैकड़ों छात्र व शोधार्थी उपाधि प्राप्त करके भारत देश की सेवा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब जो अनमने ढंग से इस पहल की आलोचना करते रहे होंगे उनके लिए भी एक लेशन-सीख है कि देश के लिए पहले अपने मन में इच्छा पैदा करो, उसे संजोकर उसकी संकल्पना को स्वरूप दो और फिर उसे स्थापित करके मिसाल के रूप में पेश करो। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री ने निःसंदेह यह सब किया है जिसका उदहारण त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह है। प्रत्यक्षदर्शी एनडीडीबी और इरमा बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह, गुजरात के सहकारिता मंत्री जीतूभाई वाघाणी व यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. जे.एम. व्यास ने उपाधिधारकों के साथ एक स्वप्न को साकार होते हुए नई अनुभति किया है लेकिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की प्रसन्नता की अनुभूति निःसंदेह असीमित होगी क्योंकि सहकारिता के नए आकाश में नई उड़ान की यह देशव्यापी हर्ष व उल्लास की बेला है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

**प्रधान संपादक**
उमेश त्रिवेदी
**कार्यकारी प्रधान संपादक**
अजय बोकिल
**संपादक (मध्यप्रदेश)**
विनोद तिवारी
**वरिष्ठ संपादक**
पंकज शुक्ला
**प्रबंध संपादक**
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

लोक संगीत

# के. सी. मालूः लोकधुनों के संरक्षक का अवसान

राजेन्द्र शर्मा

जयपुर के रहनवासी केशरी चंद मालू जीवन भर राजस्थाहन के मरुभूमि में उठती मांगणियारों और लंगाओं की स्वर-लहरियां, विवाह के अवसर पर स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत, सावन,गणगौर की आराधना, तेजाजी की लोकगाथाएं, और भक्ति में डूबे मीरा के पद, जो राजस्था न की पहचान है,को संरक्षित करने का दुरुह कार्य पचास वर्ष तक अनवरत किया और मंगलवार की पूर्वान्हष में अपने इसी काम को करते हुए हृदय गति रुकने से इस फानी दुनिया से रुखसत हो गये ।

चार जुलाई 1946 को चुरु जिले के सुजानगढ़ में जन्मे केशरी चंद मालू, जिन्हें लोग के. सी. मालू के नाम से पुकारते थे,युवावस्थाि से ही लोक संगीत के दीवाने थे। उन्हेंल यह समझ आ गया था कि लोक परंपराओं से जुडे लोक संगीत की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वे लंबे समय तक स्मृति और मौखिक परंपरा के सहारे जीवित रहती हैं। यदि कोई उन्हें समय रहते संजोने, रिकॉर्ड करने और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम न करे, तो बदलते समय की तेज आंधी में अनेक धुनें, बोल और स्वर हमेशा के लिए खो सकते हैं।

लोक संगीत के प्रति अपनी इस सोच के तहत के. सी. मालू ने लोक संगीत को सरंक्षित करने को ही अपना जीवन बना लिया । इसके लिए उन्हो नें 1977 में सुरसंगम संस्थार कर जनमानस को लोकसंगीत के प्रति जागरुक बनाने का काम किया। इसके लिए मालू गांव दर गांव लोक गायकों की तलाश करते, उन्हें मंच उपलब्ध कराते। अपने इस प्रयास में सफलता मिलने पर के सी मालू ने 1987 में 'वीणा म्यूरजिक' नामक कंपनी की स्थापना की और लोकगायकों की उनकी आवाज में ही लोक संगीत रिकॉर्ड कर अपने सीमित साधनों से उनकी कैसेट बाजार में लाने का जोखिम उठाया। कैसेट क्रांति के उस दौर में जब बाजार में हिंदी फिल्म संगीतका ही बोलबाला था, जब ऐसे समय में लोक संगीत की कैसेटों ने आम जनमानस के जुड जाने से लोक संगीत न केवल सरंक्षित हुआ अपितु लगभग बदहाल जीवन जी रहे लोक गायकों को मंच और पहचान मिलने के साथ आर्थिक रुप से समृद्ध होने का अवसर मिला।

लोक संगीत के प्रति असाधारण प्रतिबद्ध मालू द्वारा स्थोपित 'वीणा म्यूरजिक 'की पहचान धीरे-धीरे राजस्थान के लोक संगीत, विवाह गीतों और भक्ति संगीत के संरक्षण और प्रसार से जुड़ गई। मालू की विशेषता यह थी कि वे लोक संगीत को चमकदार बनाकर उसकी पहचान मिटाने के पक्षधर नहीं थे। उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परंपरा के मूल स्वरूप के प्रति सम्मान प्रमुख था।

लोक संगीत को अक्सर सीमित बाजार की वस्तु समझा जाता था। ऐसे दौर में मालू ने राजस्थान के लोक और भक्ति संगीत में केवल बाजार नहीं देखा, उन्होंने उसमें एक सभ्यता की स्मृति देखी।के. सी. मालू मूलतः उस पीढ़ी के प्रतिनिधि थे जिसने तकनीक को संस्कृति का विरोधी नहीं, बल्कि उसका सहयोगी बनाया। समय के साथ माध्यजम बदलते रहे, कैसेट के दौर से लेकर सीडी, वीडियो और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक संगीत की दुनिया लगातार बदलती रही,लेकिन मालू बदलती तकनीक का स्वाटगत करते हुए लोक संगीत को सरंक्षित करने के अपने काम मे जुटे रहे ।

एक समय था जब राजस्थान के किसी दूरस्थ गांव में गाया जाने वाला लोक गीत उसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहता था, के. सी.मालू ने रिकॉर्डिंग तकनीक ने उसे जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से बाहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और विदेशों तक पहुंचने की संभावनाओं के द्वार खोल दिये जिसके परिणामस्वररप डिजिटल क्रांति के वर्तमान दौर में भौगोलिक सीमाएं लगभग समाप्त हो गयी हैं। यह कहना अनुचित नही होगा कि के. सी. मालू ने राजस्था नी लोक सगीत की परंपरा और आधुनिक तकनीक के बीच पुल का काम किया।

राजस्थानी लोक संगीत को जन-जन पहुंचाने की अपनी दीवानगी में जीवन के पचास साल तक रात दिन इसी काम में जुटे रहे मालू की यह सफलता है कि आज राजस्थान के लोकगीतों की दुनिया अत्यंत विशाल है। जन्म से मृत्यु तक, ऋतुओं से त्योहारों तक, प्रेम से विरह तक और श्रम से अध्यात्म तक जीवन के लगभग प्रत्येक प्रसंग से संबधित लोक संगीत कैसेटस,सीडी, वीडियो और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्धि है ।

के. सी. मालू को उनके योगदान के लिए 'राजस्थान रत्न' सम्मान से भी सम्मानित किया गया। लेकिन किसी सांस्कृतिक व्यक्तित्व का वास्तविक मूल्य पुरस्कारों की संख्या से निर्धारित नहीं होता। इस धरती पर जन्माा हर मनुष्य मृत्युर की नियति से बंधा है। के. सी. मालू चले गये लेकिन जब राजस्थान का कोई पारंपरिक विवाह गीत बजेगा, जब कोई प्रवासी राजस्थानी दूर देश में अपनी मिट्टी की धुन सुनकर भावुक होगा, जब कोई युवा पहली बार किसी पुराने लोकगीत को डिजिटल माध्यम पर खोजेगा, जब किसी भूले-बिसरे लोक कलाकार की रिकॉर्ड की गई आवाज नई पीढ़ी तक पहुंचेगी–तब कहीं न कहीं के. सी. मालू की सांस्कृतिक साधना भी उपस्थित होगी।

धर्म आयोजन

डॉ. भूपेंद्र कुमार सुल्लेरे

# जगन्नाथ रथयात्रा : भारत की राष्ट्रीय एकत्व का जीवंत प्रतीक

**पुरी स्थित जगन्नाथ धाम भारत के चार प्रमुख धामों में से एक है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। यह धाम केवल वैष्णव परंपरा का केंद्र नहीं, बल्कि शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध और जनजातीय संस्कृति के अद्भुत समन्वय का केंद्र भी है। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्रीकृष्ण का लोकमंगलकारी स्वरूप माना जाता है। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिष्ठा भारतीय परिवार व्यवस्था, भाई-बहन के स्नेह और पारिवारिक एकता का संदेश देती है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ तीन भव्य रथों में आरूढ़ होकर श्रीमंदिर से लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, बलभद्र का तालध्वज और सुभद्रा का दर्पदलन कहलाता है। प्रत्येक वर्ष इन तीनों रथों का निर्माण नए सिरे से किया जाता है। इनके निर्माण की प्रक्रिया अक्षय तृतीया से प्रारंभ होती है और परंपरागत शिल्पकार बिना आधुनिक मशीनों के इन्हें तैयार करते हैं।**

चल पड़ा जब नीलचक्र, साथ चला संसार, जाति-भेद सब मिट गए, खुल गए प्रेम-द्वार। जग के नाथ की यह यात्रा, मानवता का मान, समरसता का मंत्र है, भारत की पहचान। भारत की सनातन संस्कृति में पर्व और उत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि वे समाज, संस्कृति, प्रकृति और राष्ट्र जीवन के मार्गदर्शक भी हैं। इन्हीं उत्सवों में ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा विश्व की सबसे प्राचीन और विशाल धार्मिक यात्राओं में से एक है। यह केवल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के नगर भ्रमण का उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी चेतना, सामाजिक समरसता, जनजातीय परंपरा, पर्यावरण संरक्षण तथा राष्ट्रीय एकात्मता का सजीव प्रतीक है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु, देश-विदेश से पुरी पहुँचकर इस महायात्रा में सहभागी बनते हैं और भगवान के रथ को खींचकर स्वयं को धन्य मानते हैं।

भारत में धार्मिक पर्वों का उद्देश्य केवल पूजा-अर्चना नहीं, बल्कि समाज को जोड़ना, समानता का संदेश देना और जीवन मूल्यों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाना रहा है। जगन्नाथ रथयात्रा इस परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस यात्रा में न कोई ऊँच-नीच है, न कोई जातिगत भेद, न राजा और न ही प्रजा का अंतर। सभी भगवान के सेवक बनकर एक ही रस्सी पकड़ते हैं। यही भारतीय संस्कृति की आत्मा है।

पुरी स्थित जगन्नाथ धाम भारत के चार प्रमुख धामों में से एक है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। यह धाम केवल वैष्णव परंपरा का केंद्र नहीं, बल्कि शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध और जनजातीय संस्कृति के अद्भुत समन्वय का केंद्र भी है। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्रीकृष्ण का लोकमंगलकारी स्वरूप माना जाता है। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिष्ठा भारतीय परिवार व्यवस्था, भाई-बहन के स्नेह और पारिवारिक एकता का संदेश देती है।

आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ तीन भव्य रथों में आरूढ़ होकर श्रीमंदिर से लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, बलभद्र का तालध्वज और सुभद्रा का दर्पदलन कहलाता है। प्रत्येक वर्ष इन तीनों रथों का निर्माण नए सिरे से किया जाता है। इनके निर्माण की प्रक्रिया अक्षय तृतीया से प्रारंभ होती है और परंपरागत शिल्पकार बिना आधुनिक मशीनों के इन्हें तैयार करते हैं।

रथयात्रा की सबसे अनूठी परंपरा च्छेरा पहराज है। इसमें पुरी के गजपति महाराज स्वयं स्वर्ण झाड़ू लेकर भगवान के रथ के आगे मार्ग की सफाई करते हैं। यह दृश्य भारतीय लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत प्रतीक है। राजा स्वयं को भगवान का सेवक मानते हुए झाड़ू लगाता है। इससे बड़ा सामाजिक समानता और सेवा भाव का संदेश संसार में दुर्लभ है।

**जगन्नाथ संस्कृति की आत्मा है आदिवासी समाज**– जगन्नाथ परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका मूल जनजातीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अनेक इतिहासकारों, धार्मिक परंपराओं और 'मदला पांजी' जैसे ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूल उपासना नीलमाधव के रूप में शबर (सबर/सौरा) जनजाति द्वारा की जाती थी। पौराणिक कथा के अनुसार शबर जनजाति के प्रमुख विश्ववसु भगवान नीलमाधव के महान उपासक थे। वे घने वन में गुप्त रूप से भगवान की पूजा करते थे। मालवा के राजा इन्द्रद्युम्न को जब भगवान नीलमाधव के विषय में ज्ञात हुआ, तब उन्होंने अपने पुरोहित विद्यापति को भगवान की खोज में भेजा। विद्यापति ने विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह किया और विश्ववसु के साथ वन में जाकर भगवान के दर्शन किए। बाद में भगवान ने स्वयं राजा इन्द्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन देकर समुद्र से प्राप्त पवित्र दारु (लकड़ी) से अपनी प्रतिमा बनाने का निर्देश दिया।

यह कथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि भारतीय संस्कृति ने जनजातीय समाज की आस्था को सम्मान दिया और उसे मुख्यधारा में प्रतिष्ठित किया। आज भी जगन्नाथ मंदिर की अनेक परंपराओं में शबर समाज के वंशजों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

जगन्नाथ मंदिर के दैतापति सेवक स्वयं को विश्ववसु शबर का वंशज मानते हैं। भगवान के स्नान पूर्णिमा के बाद जब वे 'अनासार' काल में विश्राम करते हैं, तब उनकी सेवा दैतापति ही करते हैं। नवकलेवर के समय पवित्र नीम वृक्ष की खोज, नई प्रतिमाओं का निर्माण, ब्रह्म परिवर्तन तथा अनेक गोपनीय धार्मिक अनुष्ठानों में दैतापति समाज की प्रमुख भूमिका होती है। रथयात्रा में भगवान को रथ पर विराजमान कराने का अधिकार भी इन्हीं सेवकों को प्राप्त है। यह भारत में जनजातीय समाज के सम्मान और सहभागिता का अद्वितीय उदाहरण है।

**पर्यावरण संरक्षण का संदेश** – जगन्नाथ रथयात्रा भारतीय पर्यावरणीय दृष्टि का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रत्येक वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं, किन्तु उनके निर्माण में प्रकृति के संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाता है। परंपरागत रूप से चयनित नीम सहित विशिष्ट वृक्षों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। निर्माण कार्य में स्थानीय कारीगरों की पीढ़ियों से चली आ रही शिल्प परंपरा का पालन किया जाता है। प्राकृतिक रंगों, कपड़ों और हस्तकला का प्रयोग भारतीय संस्कृति की पर्यावरण-सम्मत जीवन शैली को दर्शाता है।

**लोककला और स्वदेशी परंपरा का संरक्षण** – रथ निर्माण केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि लोकशिल्प का जीवंत विश्वविद्यालय है। बढ़ई, चित्रकार, मूर्तिकार, वस्त्र कलाकार और पारंपरिक शिल्पी महीनों तक मिलकर इन रथों का निर्माण करते हैं। यह परंपरा स्थानीय रोजगार, स्वदेशी शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखती है।

**राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक** – जगन्नाथ धाम भारत की सांस्कृतिक एकता का अद्भुत उदाहरण है। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, उनकी कर्मभूमि द्वारका रही, जबकि जगन्नाथ के रूप में उनकी आराधना पुरी में होती है। उनकी बहन सुभद्रा का संबंध हस्तिनापुर से जुड़ता है और विभीषण की उपासना श्रीलंका तक सांस्कृतिक संबंध स्थापित करती है। इस प्रकार उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक धाराएँ जगन्नाथ परंपरा में एकाकार हो जाती हैं।

**संघर्ष, विध्वंस और पुनर्निर्माण की गाथा** – जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों का लक्ष्य भी बना। मध्यकाल में इस मंदिर पर अनेक बार हमले हुए। इलियास शाह, फिरोज शाह तुगलक, इस्माइल गाजी, काला पहाड़ तथा औरंगज़ेब के काल में मंदिर को भारी क्षति पहुँचाई गई। अनेक बार भगवान की प्रतिमाओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। इन कठिन परिस्थितियों में स्थानीय जनता, गजपति राजाओं, पुजारियों और विशेष रूप से जनजातीय समाज ने भगवान की प्रतिमाओं की रक्षा की।

इतिहास में अनेक अवसरों पर शबर और अन्य वनवासी समुदायों ने प्रतिमाओं को जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षित रखा। इससे स्पष्ट होता है कि जगन्नाथ केवल राजाओं के नहीं, बल्कि जनजातीय समाज और सामान्य जनता के भी आराध्य थे। मुगल शासन के पतन के बाद मराठों ने मंदिर के संरक्षण का कार्य किया तथा इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने भी मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

**आज के भारत के लिए प्रेरणा** – आज जब विश्व जातीय और धार्मिक संघर्षों से जूझ रहा है, तब जगन्नाथ रथयात्रा समरसता, सहअस्तित्व और सांस्कृतिक एकात्मता का संदेश देती है। यहाँ राजा भी सेवक है, आदिवासी भी भगवान का आत्मीय है, ब्राह्मण भी सेवक है और सामान्य श्रद्धालु भी समान अधिकार से भगवान के रथ को खींचता है। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का चलता-फिरता दर्शन है। इसमें धर्म है, दर्शन है, लोकजीवन है, पर्यावरण संरक्षण है, आदिवासी समाज का सम्मान है, सामाजिक समरसता है और राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश है। यह महापर्व हमें बताता है कि भारत की शक्ति उसकी विविधताओं में नहीं, बल्कि उन विविधताओं के समन्वय में निहित है। जब समाज के सभी वर्ग एक ही रस्सी पकड़कर भगवान के रथ को आगे बढ़ाते हैं, तब वह केवल रथ नहीं चलता, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और मानवता का शाश्वत संदेश भी आगे बढ़ता है। यही जगन्नाथ रथयात्रा का वास्तविक दर्शन है और यही इसकी सनातन प्रासंगिकता।

उपलब्धि

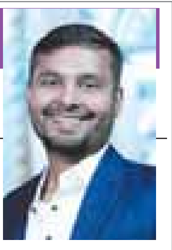

सुदर्शन व्यास

लेखक पत्रकार एवं शोधार्थी हैं।

# उच्च सदन में गूंजेगी 'माखन के लाल' की बुलंद आवाज़

जुलाई का महीना था। कोविड के प्रकोप से आमजन धीरे-धीरे उबर रहे थे। जहाँ गर्मी का पारा उतर चुका था, तो वहीं मध्यप्रदेश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा था। राज्य में 28 विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ ज़ोरों पर थी। मैंने बतौर प्रोफेशनल सोशल मीडिया विभाग में ज्वाइनिंग ली थी। रोज़ाना सुबह 10 बजे मीडिया व सोशल मीडिया की दृष्टि से पं. दीनदयाल परिसर में दिनभर के एजेण्डे पर बैठक होती और संयोगवश मैं वहाँ अपेक्षित था। बैठक के पहले ही दिन भाजपा वरिष्ठ नेता एवं तत्कालीन सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी श्री शैलेन्द्र शर्मा जी ने मुझे रजनीश भाईसाहब से मिलवाया। मुझे ज़ोर देते हुए कहा कि रजनीश जी ऐसे विचारक हैं जिनसे कभी-भी और कहीं-भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। बातें खूब हुई लेकिन वो रजनीश भाईसाहब से वो मेरी पहली भेंट थी। उस समय उनके पास भाजपा मीडिया के मुख्य प्रवक्ता का दायित्व था। उनकी सहजता और आत्मीयता से वो पहली और यादगार भेंट मुझे पहली नहीं लगी। नैरेटिव, एजेंडे समेत अन्य कार्यों पर उनका सहज मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा।

सच कहूँ तो राजनीति के विस्तृत आकाश में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो मंच की चकाचौंध से दूर रहकर भी अपने कर्म, विचार और संगठनात्मक क्षमता से अमिट छाप छोड़ जाते हैं। रजनीश अग्रवाल ऐसे ही व्यक्तित्व हैं, जिनकी राजनीतिक यात्रा यह विश्वास दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल भाषणों से नहीं, बल्कि कार्य के प्रति समर्पण, अनुशासन और निरंतर परिश्रम से निर्मित होता है।

भाजपा द्वारा मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए उनका चयन उन बीते वर्षों की साधना का सम्मान है जो उन्होंने संगठन के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित किए। रजनीश जी की सबसे बड़ी पहचान उनकी संगठनात्मक दक्षता है। भारतीय जनता पार्टी में वर्ष-2021 में बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालते हुए 'बूथ विस्तारक अभियान' को मध्यप्रदेश में सफलतापूर्वक संपन्न कराने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। संगठनात्मक दृष्टि से 65 हजार बूथों के डिजिटलाइजेशन करने के साथ ही पन्ना एवं अर्धपन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर घर - घर में कार्यकर्ता की फौज खड़ी करने में उनकी प्रभावी भूमिका रही। भाजपा में उनके समकक्षी नेता उन्हें विनोदभाव में 'बूथ का भूत' कहते हैं। तो कई उन्हें 'वर्तमान के दीनदयाल' भी कहते हैं क्योंकि उनका चेहरा कुछ - कुछ दीनदयाल जी से भी मेल खाता है। वे उन विरले नेताओं में हैं जो जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल की वास्तविक शक्ति उसके शीर्ष नेतृत्व में नहीं, बल्कि बूथ स्तर के समर्पित कार्यकर्ता में निहित होती है। संगठन के सबसे छोटे घटक को भी महत्व देने की उनकी शैली ने उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच विशेष सम्मान दिलाया है।

उनका व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली है, उतना ही सरल और सहज भी। उनसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके आत्मीय व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। राजनीति की आपाधापी और प्रतिस्पर्धा के बीच भी उन्होंने सादगी को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाए

रखा है। यही सादगी उन्हें सामान्य कार्यकर्ता से जोड़ती है। एक प्रखर वक्ता और गंभीर विचारक के रूप विचार परिवार एवं पत्रकार बिरादरी में उनकी विशिष्ट पहचान है। भाजपा की विचारधारा, राष्ट्रवाद, सुशासन और सामाजिक सरोकारों पर उनके वक्तव्य और मीडिया पर परिचर्चाएँ सदैव चर्चित रही है।

उनकी बौद्धिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जहाँ उन्होंने वर्ष 1998 से 2000 के बीच एम.ए. (प्रसारण पत्रकारिता) की शिक्षा प्राप्त की। उनकी उपलब्धियाँ ये बताती हैं कि शिक्षा डिग्री हासिल करने के साथ ही व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक पूर्व छात्र के रूप में उनकी सफलता विश्वविद्यालय परिवार के लिए भी गर्व का विषय है। वे उन युवाओं के लिए प्रेरणा हैं जो अपने सपनों को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि समाज और राष्ट्र के व्यापक हित से जोड़ते हैं। आज रजनीश जी राज्यसभा की दहलीज पर खड़े हैं। ये क्षण उन सभी कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, शिक्षकों और शुभचिंतकों के लिए भी गर्व का अवसर है जिन्होंने उनकी यात्रा को निकट से देखा है। निस्संदेह, वे राजनीति के उस शांत साधक का प्रतीक हैं, जो पद से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए रजनीश अग्रवाल का चयन केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि संगठन के प्रति उनकी दीर्घकालीन निष्ठा, परिश्रम और समर्पण का सम्मान है। मैंने देखा है कि उन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत प्रचार की अपेक्षा के संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया। रजनीश जी विश्वविद्यालय के नाते आप मेरे वरिष्ठ हैं और कर्मस्थल पर मेरे अधिकारी। उनके साथ काम करना मेरे लिए शिक्षार्जन जैसा रहा। नये राजनीतिक पड़ाव के लिये हृदयतल से बधाई।

**भाजपा द्वारा मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए उनका चयन उन बीते वर्षों की साधना का सम्मान है जो उन्होंने संगठन के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित किए। रजनीश जी की सबसे बड़ी पहचान उनकी संगठनात्मक दक्षता है। भारतीय जनता पार्टी में वर्ष-2021 में बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालते हुए 'बूथ विस्तारक अभियान' को मध्यप्रदेश में सफलतापूर्वक संपन्न कराने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।**

हमारी दुनिया

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

# विकास की भीड़ में मनुष्यता का छोटा-सा द्वीप

दुनिया का अधिकांश इतिहास इस संघर्ष का इतिहास है कि मनुष्य अधिक भूमि, अधिक संसाधन और अधिक सुविधा कैसे प्राप्त करे। सभ्यताओं ने नदियों के किनारे नगर बसाए, जंगल काटे, पहाड़ चीर दिए और समुद्र तक को पीछे धकेलकर नई जमीन बना ली। आधुनिक विकास की पूरी अवधारणा भी मानो इसी विश्वास पर टिकी है कि जीवन जितना विस्तृत होगा, उतना बेहतर होगा। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा छोटा-सा द्वीप भी है, जो इस धारणा पर मौन किंतु गहरा प्रश्नचिह्न लगाता है।

पिछले दिनों हमने यूट्यूबर और नोमेडिक टूर चैनल के वैश्विक घुमक्कड़ तोरवाशु के साथ एक अनोखे और पृथ्वी के सबसे छोटे और घने बसे द्वीप की मानस यात्रा की। कैरेबियाई सागर में कोलंबिया के तट के निकट स्थित सांता क्रूज़ डेल इस्लोटे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में गिना जाता है। लगभग दो फुटबॉल मैदान जितने क्षेत्रफल में सैकड़ों लोग रहते हैं। पहली दृष्टि में यह स्थान किसी भी नगर नियोजक के लिए अव्यवस्था का उदाहरण लग सकता है, लेकिन थोड़ा ठहरकर देखें तो यही द्वीप आधुनिक सभ्यता की कई स्थापित धारणाओं को चुनौती देता दिखाई देता है। यह केवल भूगोल का आश्चर्य नहीं, बल्कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मानवीय संबंधों की जीवित प्रयोगशाला है। इस वीडियो यात्रा ने हमे कई वैचारिक कोणों से चिंतन करने को प्रेरित किया। कहा जाता है कि लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले कुछ मछुआरों ने इस स्थान को अपना ठिकाना बनाया। धीरे-धीरे उन्होंने मूंगे, पत्थरों और अन्य सामग्री से जमीन का विस्तार किया और आज का द्वीप आकार लेने लगा। अब यहां रंग-बिरंगे छोटे मकान एक-दूसरे से सटे हुए हैं। गलियां इतनी संकरी हैं कि दो लोग मुश्किल से साथ निकल पाते हैं।

कोलंबिया के कैरेबियाई तट से कुछ दूरी पर स्थित सांता क्रूज़ डेल इस्लोटे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में गिना जाता है। लगभग 1.2 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इस छोटे-से कृत्रिम द्वीप पर सैकड़ों लोग रहते हैं। जनसंख्या के बारे में अलग-अलग अनुमान हैं, लेकिन हाल के स्थानीय आँकड़े लगभग 800 के आसपास निवासियों की ओर संकेत करते हैं।

हमने देखा कि यहां रहने वाले अधिकांश लोग अफ्रो-कोलंबियाई समुदाय से हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद लोगों के बीच सहयोग की भावना बहुत मजबूत है। अधिकांश परिवार एक-दूसरे को जानते हैं और विवाद प्रायः आपसी बातचीत से ही सुलझा लिए जाते हैं।

द्वीप पर एक प्राथमिक विद्यालय, छोटा स्वास्थ्य केंद्र, कुछ दुकानें और एक सार्वजनिक चौक है। बच्चों का बचपन समुद्र से जुड़ा होता है। वे बहुत कम उम्र से तैरना और मछली पकड़ना सीख जाते हैं।

आज महानगरों में रहने वाला व्यक्ति औसतन पहले से कहीं अधिक निजी स्थान का स्वामी है। घर बड़े हुए हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं, वाहन बढ़े हैं और सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इसके बावजूद अकेलापन, अविश्वास और मानसिक तनाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर, सांता क्रूज़ डेल इस्लोटे में रहने वाले लोग अत्यंत सीमित स्थान साझा करते हैं। वहां न कारों की आवाजाही है, न चौड़ी सड़कें और न ही निजी जीवन के लिए बहुत अधिक जगह। फिर भी वहां सामुदायिक जीवन की वह सहजता दिखाई देती है, जिसकी तलाश आधुनिक समाज लगातार करता रहता है। यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी समाज की समृद्धि का वास्तविक पैमाना क्या होना चाहिए? क्या विकास का अर्थ केवल अधिक उपभोग और अधिक निजी संपत्ति है, या फिर ऐसा सामाजिक वातावरण भी विकास का हिस्सा है, जिसमें लोग एक-दूसरे को जानते हों, सुख-दुःख में साथ खड़े होते हों और जीवन प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग पर आधारित हो?

सांता क्रूज़ डेल इस्लोटे का सामाजिक जीवन इस प्रश्न का एक व्यावहारिक उत्तर प्रस्तुत करता है। अधिकांश निवासी एक-दूसरे से परिचित हैं। विवाद प्रायः बातचीत और सामाजिक सहमति से सुलझाए जाते हैं। बच्चों का पालन-पोषण भी केवल परिवार नहीं, पूरा समुदाय मिलकर करता है। समुद्र यहां केवल आजीविका का साधन नहीं,

बल्कि सामूहिक जीवन का केंद्र है। सुबह नावों का निकलना, शाम को मछुआरों का लौटना और पूरे समुदाय का एक-दूसरे के जीवन में सहभागी होना उस सामाजिक पूंजी का निर्माण करता है, जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र अक्सर आँकड़ों में माप नहीं पाता। यहां की अर्थव्यवस्था भी विचार करने योग्य है। मछली पकड़ना आज भी जीवन का मुख्य आधार है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन ने नई संभावनाएं पैदा की हैं। दुनिया भर से लोग इस छोटे-से द्वीप को देखने आते हैं। वे यहां समुद्र की सुंदरता से अधिक मनुष्य की अनुकूलन क्षमता को देखने आते हैं। यह पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए आय का स्रोत भी है और चुनौती भी। यदि पर्यटन केवल व्यावसायिक गतिविधि बन जाए, तो वही समुदाय, जिसकी सादगी पर्यटकों को आकर्षित करती है, धीरे-धीरे अपनी मौलिक पहचान खो सकता है। इसलिए यहां आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

लेकिन इस द्वीप की कहानी केवल प्रेरणा की कहानी नहीं है। यह चेतावनी की कहानी भी है। सीमित भूमि, पेयजल की कमी, स्वच्छता की चुनौतियां और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव यहां के लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन है। समुद्र का बढ़ता जलस्तर भविष्य में ऐसे छोटे द्वीपों के अस्तित्व को ही संकट में डाल सकता है। विडंबना यह है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार समुदाय ही उसके सबसे बड़े शिकार बनते जा रहे हैं। इस अर्थ में सांता क्रूज़ डेल इस्लोटे केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पर्यावरणीय अन्याय का प्रतीक भी है।

यह द्वीप शहरी नियोजन पर भी नए सिरे से विचार करने का अवसर देता है। आधुनिक शहरों में स्थान बढ़ता जा रहा है, लेकिन सामाजिक दूरी भी बढ़ रही है। ऊंची-ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग वर्षों तक अपने पड़ोसियों के नाम तक नहीं जानते। इसके विपरीत इस छोटे-से द्वीप पर निजी स्थान सीमित है, लेकिन सामाजिक निकटता बहुत गहरी है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भीड़ आदर्श स्थिति है, बल्कि यह समझना चाहिए कि किसी समाज की गुणवत्ता केवल उसके भौतिक ढांचे से निर्धारित नहीं होती। उसके पीछे सामाजिक विश्वास, साझा जिम्मेदारी और सामुदायिक संस्कृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

भारत जैसे देश के लिए भी इस द्वीप का अनुभव प्रासंगिक है। हमारे गांवों और पुराने मोहल्लों में कभी इसी प्रकार की सामुदायिक संस्कृति दिखाई देती थी। लोग एक-दूसरे के घर बिना औपचारिकता के चले जाते थे, बच्चों की देखभाल पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी मानी जाती थी और संकट आने पर समाज सबसे पहले खड़ा होता था। शहरीकरण और उपभोक्तावाद ने इस संस्कृति को धीरे-धीरे कमजोर किया है। आज हमारे पास पहले से कहीं अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन सामाजिक आत्मीयता का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है।

सांता क्रूज़ डेल इस्लोटे हमें यह भी सिखाता है कि विकास का प्रश्न केवल आर्थिक नहीं, नैतिक भी है। यदि विकास मनुष्य को समाज से काट दे, प्रकृति से दूर कर दे और उसे केवल उपभोक्ता बनाकर छोड़ दे, तो उसकी चमक कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, वह अधूरी ही रहेगी। दूसरी ओर, यदि सीमित संसाधनों में भी मनुष्य सहयोग, विश्वास और साझा उत्तरदायित्व के साथ जीवन जीना सीख ले, तो वही समाज अधिक टिकाऊ और अधिक मानवीय बन सकता है। संभव है कि भविष्य में यह छोटा-सा द्वीप जलवायु परिवर्तन, पर्यटन और संसाधनों के दबाव के कारण अनेक कठिन चुनौतियों का सामना करे। फिर भी यह दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ता है। सभ्यता की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जाएगी कि हमने कितनी ऊंची इमारतें बनाई हैं या कितना बड़ा आर्थिक उत्पादन किया है। उसकी असली कसौटी यह होगी कि क्या हमने मनुष्यों के बीच विश्वास बचाए रखा, क्या हमने प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखा और क्या हमने सीमित संसाधनों वाली पृथ्वी पर साझा जीवन जीने की कला सीखी।

शायद इसी कारण कैरेबियाई सागर के बीच बसा यह छोटा-सा द्वीप दुनिया के सबसे बड़े महानगरों से भी बड़ा संदेश देता है। वह बताता है कि मनुष्य का भविष्य केवल अधिक जगह पाने में नहीं, बल्कि उपलब्ध जगह को अधिक मानवीय बनाने में छिपा है। यही संदेश आज की दुनिया को सबसे अधिक सुनने की आवश्यकता है।

# आत्महत्या केस में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

- **एडीजे कोर्ट ने मायके पक्ष के आरोपों को गंभीर बताया, ससुराल पक्ष को नहीं मिली राहत**

**बैतूल।** आमला की रंजिता यादव (37) आत्महत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) संतोष चौहान की अदालत ने मृतका के ससुर, सास और देवरानी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। बता दे कि रंजिता यादव 3 जुलाई को अपने घर के बाथरूम में फंदे पर लटकी मिली थीं। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मायके पक्ष ने सास, ससुर और देवरानी पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। पुलिस जांच के बाद आमला थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 और 3(5) के तहत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर ने बताया कि अपराध क्रमांक 287/2026 में एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इधर अग्रिम जमानत याचिका मृतका के ससुर, सास, और देवरानी ने दायर की थी। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि रंजिता लंबे समय से डिप्रेशन, एंग्जायटी और ओवरथिंकिंग जैसी मानसिक समस्याओं से जूझ रही थीं। उनका इंदौर और नागपुर में मनोचिकित्सकों से इलाज भी चल रहा था। बचाव पक्ष का कहना था कि ससुराल पक्ष ने कभी प्रताड़ित नहीं किया और आत्महत्या का कारण उनकी मानसिक स्थिति थी। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि मामला गंभीर है और आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं। अभियोजन ने यह भी बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

## अग्निवीर क्लर्क, एसकेटी भर्ती रैली 11 अक्टूबर को

**बैतूल।** सेना भर्ती कार्यालय भोपाल द्वारा अग्निवीर क्लर्क /एसकेटी श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली का आयोजन 11 अक्टूबर को इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में किया जाएगा। सेना द्वारा 1 जून से 12 जून 2026 तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईई आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर 12 जुलाई 2026 को जॉइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया। ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब शारीरिक दक्षता परीक्षा सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगे। रैली के लिए पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 14 जुलाई 2026 को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दिए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल ने चयनित अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर रैली स्थल पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। यह भर्ती रैली मध्य प्रदेश के अशोकनगर, भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, गुना, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, पन्ना, पांढुर्ना, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा सहित 15 जिलों के अग्निवीर (क्लर्क/एसकेटी) श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि एवं समय के अनुसार ही रैली स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र, रैली अधिसूचना के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेज, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर वाला स्मार्टफोन तथा इंटरनेट कनेक्शन साथ लाना अनिवार्य होगा।

## आमला एवं मुलताई में भूतपूर्व सैनिकों की बैठक 17 जुलाई को

**बैतूल।** भूतपूर्व सैनिकों की बैठक 17 जुलाई को आमला जनपद पंचायत सभा कक्ष में प्रातः 11 बजे से तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुलताई में दोपहर 12.30 बजे से आयोजित होगी। कैप्टन आईएन सुमीत सिंह सेवानिवृत्ति जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने आमला एवं मुलताई के भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों की पत्नियों से यथा समय बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

# शाहपुर के साप्ताहिक बाजार में डलवाई मुरम, बजरी

**बैतूल।** शाहपुर नगर के साप्ताहिक बाजार में कीचड़ और जलभराव होने की समस्या को देखते हुए नगर परिषद शाहपुर ने मंगलवार को जलभराव एवं कीचड़ वाले स्थानों पर मुरम और बजरी डालकर व्यवस्था सुधारी है। नगर परिषद के इस कदम से लोगों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली।

### मीडिया में उठी थी व्यापारियों की समस्याएं..

नगर के साप्ताहिक बाजार में बारिश के कारण कीचड़ और जलभराव की स्थिति और व्यापारियों तथा ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए पिछले दिनों अखबारों में इस समस्या की खबरों को प्रमुखता से उठाया गया था जिस पर कलेक्टर ने संज्ञान लेकर नगर परिषद के अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए थे। इस पर नगर परिषद के सीएमओ एस.आर. पंडागरे ने नगर परिषद की टीम के साथ मौके का निरीक्षण कर जलभराव तथा कीचड़ वाले स्थानों पर मुरम डालकर भराव करवाया। इससे अब व्यापारियों और नागरिकों को साप्ताहिक बाजार में आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी।

### समस्या का स्थाई हल जरूरी..

नगर के साप्ताहिक बाजार में कीचड़ और जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसके कारण व्यापारियों को हर साल बारिश के दिनों में दुकान लगाने और ग्राहकों को सामान आदि खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों द्वारा नगर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों को इस समस्या से कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक इसका सही निराकरण नहीं हो सका है। व्यापारियों का कहना है कि नगर परिषद की बैठक में इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। बाजार क्षेत्र में चबूतरे एवं टीन शेड व्यवस्थित हो जाने से लोगों को राहत मिलेगी।

**इनका कहना..**

नगर के साप्ताहिक बाजार में बारिश के दौरान कीचड़ होने और बारिश का पानी भरने की समस्या सामने आई थी, व्यापारियों ने भी इस संबंध में शिकायत की थी, इसको देखते हुए साप्ताहिक बाजार में जल भराव वाले क्षेत्र में बजरी और मुरम दलाई गई है ताकि व्यापारियों को दुकान लगाने में कोई असुविधा न हो, बाजार क्षेत्र में चबूतरे व टीन शेड आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी अध्यक्ष महोदय और सभी पार्षद गणों से चर्चा की जाएगी।

**-एस.आर. पंडाग्रे, सीएमओ, नगर परिषद, शाहपुर**

# नशे से दूरी है जरूरी 2.0 का जिले में शुभारंभ

- **पुलिस परेड ग्राउंड से निकली जागरूकता रैली, नशा मुक्ति की दिलाई शपथ**
- **नशे के खिलाफ जिले में 30 जुलाई तक चलेगा अभियान**

**बैतूल।** जिले में नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 का औपचारिक शुभारंभ 15 जुलाई को पुलिस परेड ग्राउंड से किया गया। इस अवसर पर यहां से जागरूकता रैली एवं ड्रग अवेयरनेस रन का आयोजन किया गया। पुलिस अधिक वीरेंद्र जैन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली प्रमुख मार्गो से होते वापस पुलिस ग्राउंड पहुंची। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने कहा कि नशा व्यक्ति को ही नहीं पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल और सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए। एसपी श्री जैन ने बताया कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक जिलेभर में प्रतिदिन जागरूकता रैलियां, पंपलेट वितरण, नुक्कड़ सभाएं, बैनर-पोस्टर, शॉर्ट फिल्म प्रदर्शन और अन्य जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही नशे के चिन्हित स्थलों पर पहुंचकर लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा युवाओं और अभिभावकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान के शुभारंभ एडिशनल एसपी कमलेश कुमार खरपुसे, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग सुश्री रोशनी वर्मा, एसडीओपी बैतूल अन्नपूर्णा सिरसाम, डीएसपी शेफा हाशमी सहित अन्य विभागीय अधिकारी, पुलिसकर्मी, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, खिलाड़ी उपस्थित रहे।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पालिका सहित अन्य विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं एनजीओ एवं ग्राम रक्षा समितियां 30 जुलाई तक नशे के विरुद्ध जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित करेगी। अभियान के तहत 16 जुलाई को स्कूल-कॉलेजों में रील, शॉर्ट फिल्म सहित जनजागरूकता कार्यक्रम एवं शपथ का आयोजन होगा। वहीं 17 जुलाई को व्याख्यान, लघु फिल्म प्रदर्शन तथा स्कूलों के आसपास तंबाकू-सिगरेट की गुमठियां नहीं होने का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही 18 जुलाई को झुग्गी-झोपड़ी एवं चिन्हित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, नशा पीड़ितों और उनके परिजनों को पुनर्वास केंद्रों की जानकारी तथा चिकित्सीय परामर्श दिया जाएगा तथा 19 जुलाई को ऑटो एवं शासकीय वाहनों पर पोस्टर, सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इसी प्रकार 20 जुलाई को मानव श्रृंखला बनाकर जनजागरूकता कार्यक्रम होगा तथा 21 जुलाई को चित्रकला, निबंध, पेंटिंग, स्लोगन, रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता, अभिभावकों की सहभागिता होगी। वहीं 22 जुलाई को गणमान्य व्यक्तियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के रिकॉर्डेड संदेशों का प्रचार-प्रसार तथा नशा छोड़ चुके लोगों की प्रेरक कहानियों का सोशल मीडिया पर प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा 23 जुलाई को बसों, सार्वजनिक परिवहन एवं नगर निकाय की एलईडी स्क्रीन पर जागरूकता फिल्म एवं संदेशों का प्रसारण होगा तथा 24 जुलाई को पुलिस थाना परिसरों में ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसी प्रकार 25 जुलाई को महिला एवं बाल विकास विभाग के शौर्य दल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं तथा ग्राम-नगर सुरक्षा समितियों की सहभागिता से जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा तथा 26 जुलाई को व्यापारियों, एनजीओ और सोशल ग्रुप के सहयोग से बाजार, हाट एवं सार्वजनिक स्थलों पर नशा विरोधी जनसंवाद। 27 जुलाई को शासकीय-अशासकीय छात्रावास, धार्मिक संस्थानों, फैक्ट्रियों एवं औद्योगिक इकाइयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं 28 जुलाई को वन, सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से विशेष जनजागरूकता अभियान आयोजित होगा। इसके अलावा 29 जुलाई को स्थानीय खेल प्रशिक्षकों के सहयोग से खिलाडय़ों के बीच नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम तथा 30 जुलाई को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समापन समारोह, जिसमें ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

## लायंस व लियो क्लब अमिगोज की नई टीम ने ली शपथ

- **सीए डे पर एआई के बढ़ते महत्व पर हुई चर्चा**

**बैतूल।** लायंस क्लब बैतूल अमिगोज एवं लियो क्लब बैतूल अमिगोज गोल्ड ने समाज सेवा के साथ ज्ञान और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए। एक ओर दोनों क्लबों की नई कार्यकारिणी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर जिम्मेदारियां संभालीं, वहीं सीए डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की उपयोगिता पर विशेषज्ञ व्याख्यान के माध्यम से सदस्यों को नई तकनीकों से अवगत कराया गया। 11 जुलाई को वृंदावन गार्डन में आयोजित पदग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में वरिष्ठ लायन के. आर. चौरसिया एवं जे. पी. एस. जोहर ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। लायंस क्लब बैतूल अमिगोज की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष लायन प्रजग भार्गव, सचिव लायन नीलराज पगारिया एवं कोषाध्यक्ष लायन हिमांशी धोते ने पदभार ग्रहण किया। वहीं लियो क्लब बैतूल अमिगोज गोल्ड की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष लियो मुस्कान पगारिया, सचिव लियो अनुनेय सुराना तथा कोषाध्यक्ष लियो युगल साहू ने अपने दायित्व संभाले। इसके बाद 12 जुलाई को जायका रेस्टोरेंट में सीए एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीए डे समारोह में लायंस क्लब बैतूल अमिगोज एवं लियो क्लब बैतूल अमिगोज गोल्ड ने सहभागिता की। इस अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें व्यवसाय, अकाउंटिंग, टैक्सेशन तथा दैनिक जीवन में एआई के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। वक्ता ने विभिन्न आधुनिक एआई टूल्स से परिचित कराते हुए कहा कि बदलते दौर में नई तकनीकों को अपनाना प्रत्येक व्यवसायी और प्रोफेशनल के लिए आवश्यक हो गया है। दोनों कार्यक्रमों में उपस्थित सदस्यों ने आयोजनों की सराहना करते हुए समाज सेवा के साथ-साथ ज्ञान, नवाचार और तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढने् का संकल्प लिया।

## कुनबी समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह 19 को

**बैतूल।** जिला क्षत्रिय लोणारी कुनबी समाज संगठन के तत्वावधान में जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभा सम्मान समारोह समिति के जिला अध्यक्ष प्रवीण ठाकरे, संयोजक रविशंकर पारखे ,पी .आर धोटे, नामदेव बारस्कर, व सुरेश गायकवाड ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह 19 जुलाई रविवार को शिवाजी सांस्कृतिक भवन बैतूल में आयोजित किया गया है। जिसमें समाज के कक्षा 10वीं व 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले व विशेष प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया जावेगा। इसके लिए आवेदन नवीन मेडिकल स्टोर कोठी बाजार बैतूल, तरुण एजेंसी सदर, अडलक मेडिकल, गायत्री जनरल स्टोर सदर बैतूल से प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।

# पुल नहीं बना तो चुनाव में नोटा दबाकर विरोध जताएंगे 50 गांव के ग्रामीण

**दशकों से पुल का इंतजार कर रहे ग्रामीणों का ऐलान**

**बैतूल।** भीमपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत धामन्या में ताप्ती नदी पर पुल निर्माण की वर्षो पुरानी मांग अब जन आंदोलन का स्वरूप लेने लगी है। आजादी के दशकों बाद भी पुल के अभाव में विकास की मुख्यधारा से कटे 40 से 50 गांवों के हजारों ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इस बार पुल निर्माण को स्वीकृति नहीं मिली तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे और आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि धामन्या और मुख्य मार्ग चुनालोहमा के बीच ताप्ती नदी पर पुल नहीं होने के कारण हर वर्ष बरसात के दौरान करीब छह माह तक आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है। इसका सीधा असर क्षेत्र के 40 से 50 गांवों पर पड़ता है, जो जिला मुख्यालय, अस्पताल, कृषि मंडी, कॉलेज और अन्य जरूरी सेवाओं से कट जाते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है, किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी आती है और गंभीर मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिलने से उनकी जान तक खतरे में पड़ जाती है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि पूरे क्षेत्र की एकमात्र बैंक शाखा चुनालोहमा में है, जो ताप्ती नदी के दूसरी ओर स्थित है। पुल नहीं होने से लोगों को बैंकिंग कार्यों के लिए उफनती नदी पार कर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पार करते समय कई छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन वर्षों से इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, जमीन पर पुल चाहिए। उनका कहना है कि यदि इस बार भी मांग अनसुनी रही तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे और चुनाव में नोटा के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे।

जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से सुना और पुल निर्माण संबंधी प्रस्ताव आवश्यक कार्रवाई के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को भेजने के निर्देश देते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। ग्राम पंचायत धामन्या के सरपंच एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्षों से विकास की आस लगाए बैठे ग्रामीण अब और इंतजार करने की स्थिति में नहीं हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में सतीश, सूरज, संतोष, जगन, सुकाली, मनिया, शिवकिशोर, कैलाश, मदनलाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

## 1.93 करोड़ की ऑनलाइन ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

**बैतूल।** बैतूल पुलिस ने 1.93 करोड़ रुपए के ऑनलाइन निवेश घोटाले में फरार चल रहे आरोपी योगेश कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीब डेढ़ साल से फरार था। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान पुलिस उसे छत्तीसगढ़ ले जाकर पूछताछ करेगी। आरोपी का वीडियो भी सामने आया है। मामला 9 फरवरी 2025 को सामने आया था। गंज क्षेत्र के भग्गूढाना निवासी कुलदीप राठौर ने बैतूल बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने रोबोट्रेड नाम के ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए निवेश पर ज्यादा मुनाफा देने का झांसा दिया था। शुरुआत में ऐप पर निवेश बढ़ता हुआ और मुनाफा मिलता हुआ दिखाया गया। इससे निवेशकों का भरोसा जीत लिया गया। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा कराए गए। जब पीड़ित ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो निकासी रोक दी गई। बाद में आरोपियों से संपर्क भी टूट गया। तब करीब 1.93 करोड़ रुपए की ठगी का पता चला। पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान मुख्य आरोपी मिलन राठौर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा पंकज उर्फ ज्ञानप्रकाश साहू को भी गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस ने फरार आरोपी योगेश कुमार साहू (35), निवासी पामवुड रेसिडेंसी, कातुलबोर्ड, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार किया है।

## मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की 19 को बैतूल से रवाना होगी ट्रेन

**बैतूल।** मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत हरिद्वार के लिए एक 14 बोगी की स्पेशल ट्रेन 19 जुलाई को बैतूल से सुबह 10.10 पर प्रारंभ होगी। यह ट्रेन इटारसी, बीना, विरांगना लक्ष्मीबाई नगर, आगरा कैंट, देवबंद, रुडक़ी होते हुए 20 तारीख को 14.30 पर हरिद्वार पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 21 जुलाई को हरिद्वार से 20.00 बजे निकलेगी एवं रुडक़ी, देवबंद, आगरा कैंट ,बीना, इटारसी होते हुए बैतूल 22 जुलाई को 23.40 पर आएगी।

## खाद की कालाबाजारी और ई-टोकन व्यवस्था पर किसान संघ का विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी

**भारतीय किसान संघ ने शासन को दिया अल्टीमेटम**

**बैतूल।** बडोरा मंडी में भारतीय किसान संघ, मध्य भारत प्रांत की जिला इकाई ने किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संगठन ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी, खाद की कालाबाजारी, उर्वरक वितरण व्यवस्था और वर्ष 2025 की खराब खरीफ फसल से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर किसान संघ अनिश्चितकालीन धरना-आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन में कहा कि संगठन किसानों का, किसानों द्वारा और किसानों के लिए संचालित एक गैर-राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन है, जो समय-समय पर किसानों की समस्याओं से शासन-प्रशासन को अवगत कराता रहा है। वर्तमान में किसानों के सामने कई गंभीर समस्याएं हैं, जिनका तत्काल समाधान आवश्यक है। ज्ञापन में मांग की गई है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर शत-प्रतिशत की जाए अथवा वर्ष 2025 की तरह वर्ष 2026 में भी 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से खरीदी शुरू की जाए। इसके साथ ही खाद की कालाबाजारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। किसान संघ ने ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से उर्वरक वितरण में एसएसपी और डीएपी खरीदने की अनिवार्यता समाप्त करने की भी मांग की है। संगठन का कहना है कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाए तथा प्रत्येक विकासखंड में मांग के अनुरूप पर्याप्त खाद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में वर्ष 2025 की खरीफ फसल खराब होने का भी उल्लेख करते हुए कहा गया कि प्रभावित किसानों को अब तक संबंधित लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। संगठन ने इस लंबित मामले का शीघ्र निराकरण कर किसानों को उनका हक दिलाने की मांग की है। भारतीय किसान संघ ने शासन-प्रशासन से सभी मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि समस्याओं का समय रहते निराकरण नहीं किया गया तो संगठन अनिश्चितकालीन धरना-आंदोलन शुरू करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

# खाद-बीज दुकानों का करें नियमित निरीक्षण : कलेक्टर

## ■ समय-सीमा वाले प्रकरणों का त्वरित निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

- आपदा राहत के प्रकरणों में जल्द प्रदान की जाए राहत राशि - कलेक्टर
- नर्मदा घाटों पर निर्मित करें स्वच्छता का वातावरण - कलेक्टर
- कलेक्टर की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित

**सीहोर (निप्र)।** कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के समय-सीमा वाले प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, राजस्व मामलों, वन अधिकार अधिनियम, भू-अर्जन, राहत प्रकरणों तथा वर्षाकालीन व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं से जुड़े सभी प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए तथा किसी भी स्तर पर प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखा जाये।

बैठक में कलेक्टर ने भू-अर्जन, रेलवे भूमि मुआवजा वितरण, सीएम हेल्पलाइन, वन अधिकार अधिनियम तथा अन्य राजस्व प्रकरणों में अधिक पेंडेंसी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व अधिकारियों और जिला परिवहन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे तत्परता और गंभीरता के साथ लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने राजस्व एवं वन विभाग को निर्देश दिए कि वन अधिकार पट्टों के फौती की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने वन अधिकार के सामुदायिक दावों को वन मित्र पोर्टल पर दर्ज किया जाए।

उन्होंने वन अधिकार समितियों (एफआरसी) से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी जनपदों के सीईओ को आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय भूमि की मांग से जुड़े मामलों में उपयुक्त भूमि का शीघ्र चिन्हांकन कर त्वरित भूमि आवंटन की कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने वन व्यवस्थापन से संबंधित लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्षाकालीन व्यवस्थाओं की विशेष समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि जिले के सभी बांधों, झरनों, नदियों तथा अन्य जोखिमपूर्ण स्थलों पर प्रतिबंधित आवागमन का सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान किसी भी स्थिति में लोगों को जोखिमपूर्ण स्थानों पर जाने न दिया जाए तथा सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने इस दिशा में बुधनी क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार प्रभावी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि वर्षा के दौरान ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे नागरिकों, विशेषकर बच्चों को नदी-नाले पार करने जैसी जोखिमपूर्ण स्थिति का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी विभागों के मैदानी अमले को मुख्यालय पर उपस्थित रहकर लगातार फील्ड में सक्रिय रहने तथा किसी भी आपदा अथवा दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि जान माल के नुकसान को रोका जा सके। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आरबीसी के प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाही करते हुए राहत राशि का प्रदान की जाए। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में तैयार कर भेजने के निर्देश भी दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों को नदी, तालाब, झरनों तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बैठक में जिले के नर्मदा नदी के घाटों की स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि घाटों पर स्वच्छ वातावरण विकसित किया जाए। कचरे के नियमित निष्पादन एवं सफाई के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए नवाचारों के प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाएं, ताकि स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि विभाग के अधिकारी खाद-बीज की दुकानों का नियमित निरीक्षण करें और अनियमितताएं पाए जाने पर कड़ी कर्रवाई करें। बैठक में आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान कुबेरेश्वर धाम में होने वाले आयोजन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव, अपर कलेक्टर श्री बृजेश सक्सेना, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, श्री रविंद्र परमार, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, श्रीमती स्वाति मिश्रा सहित सभी संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

## संक्षिप्त समाचार

### मौसमी बीमारियों के संबंध में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में अंर्तविभागीय बैठक सम्पन्न

**रायसेन (निप्र)।** जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में अंतरविभागीय बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सीएमएचओ सहित संबंधित अधिकारियों से कहा कि बारिश के मौसम में मलेरिया, डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण की जाएं। साथ ही सभी शासकीय अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, यह भी भी सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कहा कि जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी है कि पेयजल स्त्रोतों की नियमित जांच की जाए। साथ ही दूषित पानी से बचाव के लिए क्लोरीन की गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाए। नागरिकों को विभिन्न माध्यम से मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु जागरूक किया जाए। बैठक में सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु की जा रहीं तैयारियों से अवगत कराया गया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी तथा संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

### विदिशा में यातायात व्यवस्था सुधारने सड़क का निरीक्षण, 6 वाहनों पर चालानी कार्रवाई

**विदिशा (निप्र)।** कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार आज डिप्टी कलेक्टर श्री अजय पाठक के नेतृत्व में यातायात पुलिस के संयुक्त समन्वय से विदिशा नगर में स्वामी विवेकानंद चौराहा से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय तक मुख्य सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क पर अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों, यातायात बाधाओं तथा आवागमन की स्थिति का जायजा लिया गया। आम नागरिकों और वाहन चालकों की सुविधा तथा यातायात सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा है कि शहर में सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार के निरीक्षण और अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि वे यातायात नियमों का पालन कर प्रशासन के प्रयासों में सहयोगप्रद करें।

### लापरवाही पर शोकॉज नोटिस के निर्देश

**विदिशा (निप्र)।** कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को लंबित आवेदनों एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने विभागवार लंबित मामलों की स्थिति का अवलोकन किया तथा स्पष्ट कहा कि आमजन की शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान यह सामने आया कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत दर्ज कुछ शिकायतों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित अधिकारियों द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर कलेक्टर श्री गुप्ता ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर को ऐसे सभी अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ (शोकॉज) नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन शासन की प्राथमिकता वाली व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा करते हैं। इसलिए सभी अधिकारी शिकायतों का समय-सीमा में तथ्यात्मक, संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग नियमित रूप से लंबित प्रकरणों की समीक्षा करे और किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

## खाद्य विभाग ने आठनेर में खाद्य प्रतिष्ठानों से मसालों के 6 नमूने जांच के लिए भेजे

**बैतूल (निप्र)।** कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन बैतूल के खाद्य सुरक्षा प्रशासन दल ने सोमवार को आठनेर के बाजार चौक स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों एवं किराना दुकानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान व्यापारियों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने , एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री का भंडारण एवं विक्रय नहीं करने तथा नियमानुसार खाद्य लाइसेंस/पंजीयन प्राप्त कर ही कारोबार संचालित करने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के दौरान विभिन्न दुकानों से मसालों के 6 नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। दल ने खाद्य सामग्री को ढककर रखने, प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने तथा फलों की दुकानों पर सड़े-गले फल नहीं रखने के निर्देश भी दिए।

साथ ही सभी व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस दुकान पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए कहा गया। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच एवं निरीक्षण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

### अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

## मत्स्य एवं ग्रामीण विकास विभाग मिलकर करें कार्य

**विदिशा (निप्र)।** कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान जिले के अमृत सरोवरों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मत्स्य विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्य करते हुए सभी उपयुक्त अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि अमृत सरोवर केवल जल संरक्षण तक सीमित न रहें, बल्कि उनका उपयोग ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए भी किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को ऐसे सभी अमृत सरोवरों का सर्वे कर मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त जलाशयों का चिन्हांकन करने तथा आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्ययोजना बनाकर अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से शुरू कराएं, ताकि ग्रामीणों एवं मत्स्य पालकों को इसका लाभ मिल सके और अमृत सरोवरों का बहुउद्देशीय उपयोग सुनिश्चित हो। मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की पहल, जिले के 244 तालाब पट्टे पर दिए जाएंगे। विदिशा जिले में वर्ष 2026-27 के लिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तालाब एवं जलाशयों के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस वर्ष जिले में कुल 244 तालाबों एवं जलाशयों का पट्टा आवंटन किया जाएगा, जिनका कुल जलक्षेत्र 2290.54 हेक्टेयर है।

इससे मत्स्य सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों तथा पात्र मत्स्य पालकों को रोजगार एवं आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जारी जानकारी के अनुसार जिले में 224 ग्रामीण तालाब उपलब्ध हैं, जिनका कुल जलक्षेत्र 786.26 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत के अधीन 13 जलाशय हैं, जिनका जलक्षेत्र 622.50 हेक्टेयर है, जबकि जिला पंचायत के अधीन 7 जलाशय हैं, जिनका कुल जलक्षेत्र 1581.78 हेक्टेयर है। सिंचाई विभाग के जलाशयों से संबंधित इस वर्ष कोई आवंटन प्रस्तावित नहीं है। इस प्रकार जिले में कुल 244 तालाबों एवं जलाशयों का पट्टा आवंटन किया जाएगा। मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं पात्रता के अनुसार पट्टा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने पात्र मत्स्य सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों एवं इच्छुक मत्स्य पालकों से समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। इस पहल का उद्देश्य जिले में मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

## छात्रावासों में ई-लर्निंग, गुणवत्तापूर्ण भोजन, पेयजल व शौचालय की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें : कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे

### ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें

**बैतूल (निप्र)।** कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जनजातीय कार्य, लोक निर्माण, वाणिज्यिक कर, सामाजिक न्याय एवं श्रम विभाग सहित अन्य विभागों को लंबित शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टाइम-लिमिट एवं जनसुनवाई के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। लोक सेवा गारंटी के समय-सीमा से बाहर गए प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को जिले के सभी छात्रावासों में ई-लर्निंग टूल्स एवं लाइब्रेरी का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित डाइट चार्ट के अनुसार विद्यार्थियों को प्रतिदिन नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए।

साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला परियोजना समन्वयक को नव भारत साक्षरता अभियान के अंतर्गत सामाजिक चेतना केंद्रों का प्रभावी संचालन कर वयस्कों के लिए आधारभूत शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने के लिए कहा। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में समग्र आईडी एवं आधार निर्माण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा पात्र हितग्राहियों के समग्र आईडी एवं आधार प्राथमिकता से बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को समग्र आईडी, संबल पंजीयन एवं आधार जैसी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी न हो।

## सघन निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश

**विदिशा (निप्र)।** कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को आयोजित लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों को अपने-अपने क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आमजन के हितों की सुरक्षा, नियमों के प्रभावी पालन तथा अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए नियमित जांच अभियान संचालित किए जाएं और उसकी साप्ताहिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिला परिवहन अधिकारी को वाहनों की सघन जांच कर यातायात नियमों के पालन, आवश्यक दस्तावेजों तथा ओवरलोडिंग सहित अन्य अनियमितताओं की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को जिले के थोक दवा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर लाइसेंस, दवा भंडारण व्यवस्था एवं औषधि अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा विभाग को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता की जांच के लिए नियमित सैंपलिंग और निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

# प्रकरणों का समयावधि में निराकरण सुनिश्चित कराने कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

### कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में टीएल बैठक सम्पन्न

**रायसेन (निप्र)।** कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक मे कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाईन, समय सीमा वाले पत्रों, योजनाओं तथा विभागों के कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने विभागवार और अधिकारीवार सीएम हेल्पलाईन की निराकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सीएम हेल्पलाईन का शीघ्रता से संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराने हेतु निर्देशित किया। साथ ही 50 दिवस से अधिक समयावधि की शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण कराने के लिए कहा। इसी प्रकार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समयावधि के पहले ही निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने राजस्व विभाग अंतर्गत नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि प्रकरणों की तहसीलवार निराकरण की समीक्षा करते हुए तहसीलदारों को निर्देश दिए कि प्रकरणों का गंभीरतापूर्वक निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण हो और समयावधि में हो, यह सभी सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार फार्मर रजिस्ट्री की जानकारी लेते हुए सभी तहसीलदारों को कार्य में गति लाते हुए शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जनपदवार जानकारी लेते हुए सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि हितग्राहियों को किस्तों का भुगतान समय पर हो तथा हितग्राही द्वारा आवास निर्माण में ही राशि का उपयोग किया जाए, यह सुनिश्चित कराएं। बैठक में श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने संबल योजना में पंजीयन के लंबित आवेदनों की जनपद और निकायवार जानकारी लेते हुए अधिकारियों को शीघ्रता से कार्यवाही कर निराकरण करने के लिए कहा। इसी प्रकार निर्माणाधीन पंचायत भवनों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए सभी सीएमओ से कहा कि योजना के तीनों चरणों में अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। पथकर विक्रेताओं को योजना की जानकारी देते हुए आवेदन प्राप्त किए जाएं तथा स्वीकृति की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में खाद की उपलब्धता तथा वितरण की जानकारी लेते हुए कहा कि किसानों को व्यवस्थित तरीके से खाद का वितरण किया जाए। इसके साथ ही जिले में खाद विक्रय प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने तथा खाद-बीज के नमूनों की जांच कराने के भी निर्देश कृषि अधिकारी को दिए गए। इसी प्रकार सांसद निधि एवं विधायक निधि से स्वीकृत कार्यो की जानकारी लेते हुए उन्होंने कार्यो को शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिए कहा। बैठक में सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर्स तथा जिला अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखण्डों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित विकासखण्डस्तरीय अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

# लखन पटेल से पशुपालन विभाग छीना

## सीएम ने अपने पास रखा, अब सिर्फ आनंद विभाग के मंत्री रहेंगे

### पथरिया से हैं विधायक

लखन पटेल दूसरी बार विधायक बने थे। वह दमोह जिले के पथरिया से विधायक हैं। पहली बार 2013 में विधायक बने थे। फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे। मोहन सरकार में वह पहली बार मंत्री बने हैं। विधायक बनने से पहले वह एसबीआई में कृषि अधिकारी थे।

**भोपाल (नप्र)।** मध्य प्रदेश में एक बड़ा सियासी उथल-पुथल है। मोहन कैबिनेट में रातों-रात बड़ा उलट फेर हुआ है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल से उनका विभाग छीन लिया गया है। साथ ही इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। उन्हें सिर्फ आनंद विभाग दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पास पशुपालन विभाग को रखा है।

### सभी हैरान

वहीं, यह फैसला देर रात लिया गया है। अब इसकी अधिसूचना सार्वजनिक की गई है। दो बार के विधायक लखन पटेल से पशुपालन विभाग ले लिया गया है। अब उन्हें आनंद विभाग दिया गया है। पशुपालन की तुलना में इस विभाग का बजट बेहद कम होता है। इस बदलाव को लेकर कई तरहत की अटकलें हैं।

**मुख्यमंत्री पास अब पशुपालन विभाग–** सीएम मोहन यादव के पास पहले से ही कई अहम विभाग हैं। अब पशुपालन विभाग भी उन्हीं के पास चला गया है। सीएम के पास अभी सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय, पशुपालन एवं डेयरी समेत अन्य ऐसे विभाग हैं, जिनके मंत्री नहीं हैं। खबर है कि सुबह 10 बजे के करीब लखन पटेल ने सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है। इसके बाद उन्हें इस बदलाव की जानकारी दी गई है। वह पशुपालन विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे।

### मुख्यमंत्री ने इंदौर जिला अस्पताल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया

# समान कानून लागू करने की दिशा में बढ़ रही सरकार

## इंदौर में बोले- रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक की ही अपेक्षा

**भोपाल/इंदौर (नप्र)।** इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर में 300 बिस्तरीय नए जिला चिकित्सालय के लोकार्पण के दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर बड़ा बयान दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक समान कानून लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा-अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहन है। उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा। उनको क्या अलग कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि एक देश में अलग-अलग कानून नहीं होने चाहिए और सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान का विचार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर उस संकल्प को आगे बढ़ाया। अब मध्य प्रदेश भी उसी भावना के साथ एक समान कानून लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अलग-अलग समुदायों के लिए विवाह और अन्य व्यक्तिगत कानून अलग हैं, जबकि एक देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भी यह जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, हम चाहते तो इस कानून को विधानसभा से सीधे भी पारित करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने प्रदेश के सभी 55 जिलों और 10 संभागों में जाकर लोगों से संवाद किया और सुझाव लिए। इन सभी सुझावों का संकलन करने के बाद सरकार अब विधानसभा में कानून लाने की तैयारी कर रही है।

**पहले चरण में 34 बेड की विंग शुरू होगी–** करीब 83.16 करोड़ रुपए की लागत से बने चार मंजिला 300 बिस्तरीय जिला अस्पताल से पश्चिमी इंदौर के लाखों लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। हालांकि पहले चरण में केवल 34 बेड की प्रसूति (मैटरनिटी) विंग शुरू की जाएगी। अस्पताल के शेष 266 बेड और मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग समेत अधिकांश प्रमुख विभाग फिलहाल शुरू नहीं होंगे।

**38 साल बाद मिला नया अस्पताल–** धार रोड स्थित जिला अस्पताल वर्ष 1988 से दुग्ध संघ की जर्जर इमारत में संचालित हो रहा था। क्षेत्र की बढ़ती आबादी के बीच नए अस्पताल की मांग वर्षों तक उठती रही। वर्ष 2005 में पहली बार नए भवन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, लेकिन मंजूरी मिलने में ही करीब दो दशक लग गए। आखिरकार 2017 में 300 बिस्तरीय अस्पताल को स्वीकृति मिली और निर्माण शुरू हुआ, जो लगातार देरी के बाद अब पूरा हुआ है।

**18 करोड़ का प्रोजेक्ट पहुंचा 83 करोड़ तक–** शुरुआत में अस्पताल निर्माण की लागत 18 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन निर्माण में देरी, संशोधित स्वीकृतियों और अतिरिक्त कार्यों के चलते परियोजना की लागत बढ़कर 83.16 करोड़ रुपए हो गई। यानी शुरुआती अनुमान से करीब 65 करोड़ रुपए अधिक खर्च होने के बाद भी अस्पताल अपनी पूरी क्षमता के साथ शुरू नहीं हो पा रहा है।

**पहले चरण में सिर्फ प्रसूति सेवाएं–** अस्पताल भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद फिलहाल केवल 34 बेड की मैटरनिटी विंग शुरू की जा रही है। हड्डी रोग, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हृदय रोग सहित अधिकांश प्रमुख विभाग बाद में शुरू होंगे। ऐसे में इन बीमारियों के मरीजों को अभी भी एमवाय अस्पताल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

**166 अधिकारी-कर्मचारियों की तैनाती–** स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संचालन के लिए 166 अधिकारी और कर्मचारियों की पदस्थापना की है। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। स्वास्थ्य आयुक्त भी अस्पताल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी नहीं होने के कारण अस्पताल को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है।

### स्वास्थ्य कर्मचारियों को कार्यक्रम में बुलाने के निर्देश

सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने इमरजेंसी स्टाफ को छोड़कर जिले के सभी जोनल स्वास्थ्य कर्मचारियों, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को सुबह 11:30 बजे तक जिला अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। इससे अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित सेवाएं प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है।

### पश्चिमी इंदौर को मिलेगी आंशिक राहत

नए अस्पताल से चंदन नगर, नूरानी नगर, द्वारकापुरी, सिरपुर, राजेंद्र नगर सहित पश्चिमी इंदौर और आसपास के दो दर्जन से अधिक गांवों की गर्भवती महिलाओं को तत्काल राहत मिलेगी। हालांकि अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को सभी विभाग शुरू होने तक इंतजार करना होगा।

# पुलिस चेकिंग में पकड़ी स्कूटी, चोर ले भागा

## पुलिसकर्मी ने खुद सौंपी चाबी, शिकायत दर्ज कराने थाने - थाने भटक रहा फरियादी

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की कथित लापरवाही सामने आई है। 13 जुलाई को सेंट्रल लाइब्रेरी चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने स्कूटी सवार को रोका। उसकी स्कूटी की चाबी निकाल ली। बाद में यह चाबी एक अनजान व्यक्ति को दे दी, जो वाहन लेकर फरार हो गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद है।

शिकायतकर्ता नदीम आलम निवासी ललरिया तहसील बैरसिया ने पुलिस कमिश्नर को दिए आवेदन में बताया कि उसकी सुजुकी बर्गमैन स्कूटी 13 जुलाई की रात करीब 8 बजे उसके बहनोई मोहम्मद सगीर चला रहे थे। सगीर सेंट्रल लाइब्रेरी होते हुए इब्राहिमपुरा जा रहे थे। इसी दौरान सेंट्रल लाइब्रेरी चौराहे पर पुलिस की वाहन चेकिंग चल रही थी।

**वाहन चेकिंग के दौरान हुई वारदात–** वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी रोककर उसकी चाबी अपने पास रख ली और 300 रुपए का चालान बनाया। सगीर के पास तत्काल चालान की राशि नहीं थी, इसलिए उन्होंने नदीम को फोन कर पैसे बुलाए। इसी बीच शिकायतकर्ता का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने स्कूटी की चाबी किसी अज्ञात व्यक्ति को दे दी, जो स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गया।

**चार थानों में फरियाद लेकर पहुंचा पीड़ित–** नदीम का कहना है कि जब वह मौके पर पहुंचा और वाहन के बारे में जानकारी मांगी तो पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और वाहन नहीं मिलने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने कमेंट्स किया कि चाचा अब तुम्हारी गाड़ी गई। जिससे अंदाजा होता है कि वाहन को ले जाने वाले को वह पहले से ही जानते थे।ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने स्कूटी की चाबी किसी अज्ञात व्यक्ति को दे दी, जो स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गया।

**चार थानों में भटकते रहे–** इसके बाद शिकायतकर्ता वाहन की चोरी संबंधी शिकायत दर्ज कराने मंगलवारा, तलैया, हनुमानगंज और गौतम नगर थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर थाने ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उस स्थान पर उनकी टीम की ड्यूटी नहीं थी। साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी वहां चेकिंग करने की बात से इनकार कर रही है। अब उसने पुलिस कमिश्नर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने और उसकी स्कूटी बरामद कर उसे वापस दिलाने की मांग की है।शिकायतकर्ता वाहन की चोरी संबंधी शिकायत दर्ज कराने मंगलवारा, तलैया, हनुमानगंज और गौतम नगर थाने के चक्कर लगा रहा।

**हनुमानगंज का आरक्षक चेकिंग पाइंट पर था–** सीसीटीवी में दिख रहे जिस आरक्षक पर वाहन की चाबी अज्ञात युवक देने और वाहन को ले जाने देने का मौका देने के आरोप हैं, उसका नाम दिनेश डेहरिया है। वह हनुमानगंज थाने में पदस्थ है। जबकि चेकिंग मंगलवारा थाना इलाके में चल रही थी। मीडिया से बात करते हुए बताया कि चाबी अज्ञात युवक को उसने नहीं सौंपी है। चाबी वाहन में पहले से लगी थी। जिसे अज्ञात युवक ले गया। उसे नहीं पता यह युवक कौन है।

### थाना प्रभारी बोले मामले की जांच कराई जा रही

मंगलवारा थाने के प्रभारी अजय सोनी ने बताया कि जहां चेकिंग हो रही थी, वह इलाका उनके थाना क्षेत्र में आता है। मामला उनके संज्ञान में है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे।

# तीन दिनी पटवारियों की हड़ताल शुरू

## 17 तक सामूहिक अवकाश पर; 5 दिन प्रभावित रहेंगे राजस्व कार्य

**भोपाल (नप्र)।** मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने पदोन्नति, कैडर रिव्यू और अन्य लंबित मांगों को लेकर बुधवार से तीन दिवसीय आंदोलन शुरू कर दिया है। 15 से 17 जुलाई तक प्रदेशभर के पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके बाद 18 और 19 जुलाई को शासकीय अवकाश होने से लगातार पांच दिन राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित रहने की आशंका है।

**पटवारियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील–** मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने सभी जिलों के पटवारियों से एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेने की अपील की है। संघ का कहना है कि वर्षों से लंबित मांगों के समाधान के लिए शासन स्तर पर लगातार पत्राचार और आग्रह किए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

**कैडर रिव्यू और पदोन्नति प्रमुख मांगें–** संघ के अनुसार उनकी प्रमुख मांगों में कैडर रिव्यू, नियमित पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण शामिल है। पटवारियों का कहना है कि इन मांगों के पूरा होने से न केवल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राजस्व प्रशासन की कार्यक्षमता भी बेहतर होगी।

### सोशल मीडिया पर कविता के जरिए दी चेतावनी

आंदोलन के समर्थन में पटवारी संघ ने सोशल मीडिया पर एक कविता भी साझा की है, जिसमें शासन को चेतावनी देते हुए लिखा गया है—
वरना बस्ता बंद करेंगे,
कलम छोड़ रुक जाएंगे,
नक्शे सारे धरे रहेंगे,
साहब ढूंढ न पाएंगे।

### संघ बोला- अधिकारों की लड़ाई, टकराव नहीं

पटवारी संघ का कहना है कि यह आंदोलन किसी टकराव के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। इसका मकसद सरकार तक कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। संघ का कहना है कि समयबद्ध पदोन्नति और कैडर रिव्यू लागू होने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और आम नागरिकों को मिलने वाली राजस्व सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

# सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त

## नियम विरुद्ध बताकर महाधिवक्ता कार्यालय से मांगा पूरा मूल रिकॉर्ड

**जबलपुर (नप्र)।** मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय में सरकारी वकीलों की नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी के आरोपों को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिया है कि इन नियुक्तियों से जुड़ी चयन प्रक्रिया का पूरा मूल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त तय की है। कोर्ट ने इस दौरान महाधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी जारी किए हैं।

**पारदर्शिता गायब, पक्षपात के आरोप–** हाईकोर्ट की गलियारों में इस बात को लेकर लंबे समय से चर्चा थी, जो अब कोर्ट रूम तक पहुंच गई है। याचिका में साफ कहा गया है कि इन नियुक्तियों में किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं बरती गई और पूरी प्रक्रिया मनमाने व पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई। इससे पहले कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

### 10 साल के अनुभव के नियम पर सवाल

यह पूरा मामला हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के संयुक्त सचिव योगेश सोनी की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट में दलील दी कि साल 2013 की राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक, शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 साल की वकालत का अनुभव होना अनिवार्य है। आरोप है कि महाधिवक्ता कार्यालय में कई ऐसे वकीलों को रख लिया गया, जिनके पास यह निर्धारित अनुभव है ही नहीं।

### हरियाणा से बारात बुलाई, फेरे कराए फिर विदा के बाद ससुराल वालों ने ही लूट लिया, 2.25 लाख रुपए

# सोने की चेन- मोबाइल लूटे, दुल्हन भी वापस ले गए

**शिवपुरी (नप्र)।** जिले के पिछोर क्षेत्र में शादी कराने के नाम पर कथित ठगी और लूट का मामला सामने आया है। हरियाणा के एक परिवार का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उनसे 2.25 लाख रुपये, सोने की चेन और मोबाइल छीन लिया गया। इतना ही नहीं, शादी के बाद साथ ले जा रही युवती को भी उसके परिजन वापस ले गए।

### हरियाणा से शादी कराने बुलाया गया

प्रीति पत्नी सुधीर फोगाट, निवासी ग्राम घेगोंला, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम ने पुलिस को बताया कि उनके भाई योगेंद्र कुमार जाखड़ की शादी नहीं हुई थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के महरानीपुर जिले के ग्राम उलधन निवासी काशीराम अहिरवार और शैलेंद्र अहिरवार ने उनके नाना टेक सिंह से संपर्क कर शादी कराने का भरोसा दिलाया। उनकी बातों पर विश्वास कर 13 जुलाई 2026 को परिवार हरियाणा से कार से बबीना पहुंचा, जहां से दोनों आरोपी उन्हें लेकर शिवपुरी जिले के पिछोर क्षेत्र पहुंचे।

### शादी के बाद रास्ते में रोका

परिवार का आरोप है कि नयागांव चौराहे के पास एक गांव में योगेंद्र की शादी एक युवती से करा दी गई। शादी के बाद जब सभी दुल्हन को लेकर वापस लौट रहे थे, तभी रात करीब साढ़े 9 बजे युवती के परिजन और अन्य लोग रास्ते में आ गए।

### ड्राइवर का मोबाइल फोन छीन लिया, लड़की को भी ले गये

आरोप है कि उन्होंने कार रोककर पहले पैसे देने की मांग की और फिर 2.25 लाख रुपये, सोने की चेन और ड्राइवर का मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद युवती को भी अपने साथ वापस ले गए। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि उनकी कार में तोड़फोड़ की गई।

### पूरे मामले की जांच की जा रही है, पिछोर एसडीओपी

पिछोर के एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि हरियाणा से से यह लोग शादी करने के लिए आए थे।

दोनों पक्षों के बीच लेनदेन को लेकर कोई विवाद हुआ है। मामले में शिकायत आई है। हम मामले की जांच कर रहे है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।